राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 330 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, मंगलवार, 08 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

21 जून से सभी को लगेगा मुफ्त टीका, दिवाली तक मिलेगा मुफ्त अनाजः पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी सोमवार शाम 5 बजे देश को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इसमें 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाए जाने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी. देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी. प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा.

पीएम मोदी ने कहा, कोरोना जैसे अदृश्य रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार कोविड प्रोटोकॉल है. वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है. अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो भारत में क्या होता. आप पिछले 50-60 साल का देखेंगे तो पता चल जायेगा की दशकों लग जाते थे. पोलियो और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन बनाने में भी दशकों लग गए. जिस तरह टीकाकरण चल रहा था 2014 में अगर वैसे चलता तो 40 साल लग जाते, हमने मिशन इंद्रधनुष के तहत लोगों को वैक्सीन देने का कार्य किया और सिर्फ 5 साल में में ही वैक्सीनेशन 60 प्रतिशत से बढ़ कर 90 हो गया.

एक साल में 2 स्वदेशी वैक्सीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने बचों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए भारत में टीके बनवाए. उन्होंने कहा, हमें गरीबों की चिंता थी और भारत की चिंता थी. उन्होंने कहा, जब हम शत प्रतिशत टीका के लिए बढ़े तो कोरोना ने हमें घेर लिया. भारत ने 1 साल के अंदर एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखा दिया कि भारत अब पीछे नहीं है. 23 करोड़ से यादा वैक्सीन की डोज दी जी चुकी हैं.

कई मोर्चों पर एक साथ लड़े

पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक महामारी के खिलाफ कई मोर्चों पर हमारा देश एक साथ लड़ा. भारत के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी. सरकार के सभी तंत्र लगे. दुनिया भर से जो कुछ भी उपलब्ध कराया जा सकता था लाया गया. जरूरी दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाया गया.

और वैक्सीन मिलेंगी देश को

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले काफी समय से देश जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है उससे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है. आज देश में 7 कंपनियां वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं. 2 और वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है. देश में एक ह्ड्डह्यड्ड्य 1ड्डष्द्धठ्ठद्ग की तैयारी चल रही है. देश को अगर इस वैक्सीन से सफलत मिलती है तो और यादा सफलता मिलेगी. पिछली बार देश में लगाए गए लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद मिले सुझाव के बाद ही हर फैसला लिया लेकिन कई बार ये आवाज उठी कि सभी अधिकार केंद्र को क्यों? कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि बुजुर्गों को पहले वैक्सीनेशन क्यों? हमने जिनको यादा खतरा है उनको पहले वैक्सीन लगवाया. सोचिए,

अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले अगर हम डॉक्टर को वैक्सीन नहीं लगाते तो क्या होता? यादा से जयादा हेल्थ वर्कर को टीका लगा इसीलिए वो यादा से यादा देश के लोगों को बचा पाए.

लॉकडाउन आखिरी विकल्प

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी लहर के दौरान इससे पूर्व 20 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित किया था. उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रायों से लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की अपील की थी. हालांकि, लगातार बढ़ रहे मामलों और ऑक्सीजन संकट, आईसीयू बेडों की कमी आदि के कारण रायों को आंशिक लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा.

मई के आखिरी दिनों से हालात काबू में- मई के आखिरी दिनों से देश में कोरोना के मामले कंट्रोल होते दिखे हैं. अब अस्पतालों में आईसीयू बेडों को लेकर पहले की तरह मारामारी नहीं है. पहले जहां देश में तीन से चार लाख रोज केस आते थे, अब घटकर करीब एक लाख केस डेली आ रहे हैं. सोमवार को कोरोना के कुल 1,00,636 नए मामले दर्ज हुए. इस वक्त देश में 2,89,09,975 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

सीएम योगी ने जताया आभार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के इस निर्णय पर आभार जताया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व का ही सफल है कि अब देश के किसी भी राय सरकार को कोविड वैक्सीन प्राप्ति हेतु कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी. इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार.

वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने का निर्णय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को चरितार्थ करता है. उत्तर प्रदेश के समस्त लाभार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार. पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा. महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है. यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा

पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 18 लोगों की मौत

पुणे, (ईएमएस)। सोमवार दोपहर पुणे एक केमिकल फैक्ट्री एसवीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पुणे जिले के मुलशी तालुका के पिरंगुट में स्थित औद्योगिक एस्टेट में इस कंपनी में आग दोपहर 2 बजे के आसपास लगी। दमकल विभाग के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात 37 कर्मचारियों में से 19 को बचा लिया गया है। इसमें ज्यादातर महिलायें काम करती थीं। इस अग्निकांड में 18 लोगों के मौत हो गई है। केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूर से ही धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इसमें हवा, पानी और भूतल उपचार रसायन (केमिकल) का विनिर्माण, आपूर्ति और निर्यात का काम होता है। पीएमआरडीए (पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण) दमकल सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे ने कहा, कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने के बाद से उनके कम से कम 18 कर्मचारी लापता थे। दमकल अधिकारियों ने बताया कि इस प्लांट में फिलहाल सैनेटाइजर बनाने का काम किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आठ गाडियों को मौके पर भेजा गया। फिलहाल आग बुझा दी गई है और कूलिंग का काम जारी है। उन्होंने कहा कि कंपनी विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन और निर्यात करती है।

भारत अपनी एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र नीतियों में देगा योगदान : जयशंकर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र नीतियों में योगदान देगा। उन्होंने यह बात बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) दिवस पर कही।

उन्होंने ट्वीट किया कि बिम्सटेक दिवस, बंगाल की खाड़ी में सहयोग की अपार संभावनाओं को दशार्ता है। यह महसूस कराता है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को आपस में जोड़ने में मदद मिली है। यह हमारी एक्ट ईस्ट और इंडो-फैसिफिक नीतियों में भी योगदान देगा। मंत्री जयशंकर ने अप्रैल में 17वीं बिम्सटेक बैठक में शिरकत की थी और कहा था कि भारत बिम्सटेक के फ्रेमवर्क के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिम्सटेक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के सात देश सदस्य हैं। बिम्सटेक दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार व थाईलैंड के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक अनूठा संपर्क जोड़ता है।

कोविड से अनाथ हुए बचों पर पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकारों का रवैया असंवेदनशील

नई दिल्ली । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोमवार को कहा कि कोरोना वारयरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बचों को लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकारों का रवैया असंवेदनशील है क्योंकि इन्होंने इन बचों के संदर्भ में अब तक पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी रायों को बचों के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

कानूनगो ने कहा कि अनाथ बचों की मदद को लेकर कई राय सरकारों ने तेजी से काम किया है। यह अछा संकेत है कि हम बचों की मदद के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली दो राय ऐसे हैं, जहां इन बचों का सर्वे नहीं कराया गया और हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बचों के प्रति इन दोनों सरकारों के रवैये को संवेदनशील नहीं कहा जा सकता।

उल्लेखनीय है कि एनसीपीसीआर ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 मई तक रायों की ओर से प्रदान किए गए डेटा के मुताबिक 9346 ऐसे बचें है जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। एनसीपीसीआर ने ऐसे बचों की जानकारी के लिए वेबसाइट बाल स्वराज शुरू किया है जहां राय अपने यहां का डेटा उपलब्ध करा सकते हैं।

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का उल्लेख करते हुए कानूनगो ने कहा कि तीसरी लहर में बचे प्रभावित होंगे या नहीं, ये विशेषज्ञों के बताने की बात है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और बचों के इलाज से जुड़े आधारभूत ढांचा को मजबूत रखना चाहिए। उनके मुताबिक, आईसीएमआर ने हमें बचों के इलाज का प्रोटोकॉल दिया है। हम इसे पूरे देश में प्रसारित करने में लगे हैं।

अगले चार हफ्ते में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहली डोज लगा दी जाएगी : केजरीवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार, दिल्ली के 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अगले चार हफ्ते के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगा देगी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से जहां बूथ, वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर कम लोग आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने लोगों के घर-घर जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी वार्डों में स्थित पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को सेंटर तक लाने के लिए बड़ी संख्या में ई-रिक्शे का इंतजाम किया है। सीएम ने कहा कि आज से 70 वार्डों में शुरू हुए अभियान के तहत बीएलओ की टीम घर-घर जाकर पात्र लोगों को वैक्सीनेशन का स्लॉट देगी और जो वैक्सीन लगवाने से इन्कार करेंगे, उन्हें इसके लिए समझाया जाएगा। जब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन मिल जाएगी, तब हम इसी तरह से दो बार अभियान चलाकर उन्हें भी वैक्सीन लगा देंगे। सीएम ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग बढ़-चढ़कर वैक्सीन लगवाएं। यही एक तरीका है, जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर आज महत्वपूर्ण डिजिटल प्रेस कांन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम जहां वोट, वहां वैक्सीनेशन है। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई। मुझे लगता नहीं है कि वैक्सीन की कमी होगी, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फिलहाल केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, तो इस अभियान के तहत चार हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 साल के ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। अभी 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। हमने दिल्ली में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर खोलें हैं, उसमें लोग बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी समय तक खाली रहते हैं और काफी दवाई बच जाती है। इसी के मद्देनजर यह तय किया गया कि लोगों का इंतजार किए बिना अब हमें लोगों तक जाना पड़ेगा। अब हमें लोगों के घर-घर जाना पड़ेगा। इस अभियान के तहत हम लोगों के घर-घर जाएंगे।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुला गांधी ने डीजल-प्रेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार करते हुए सोमवार को कहा कि उनके शासन में टैक्स बढ़ोतरी की लहरें लगातार आ रही हैं। जिसके कारण महंगाई आसमान छू रही है और आम लोगों का जीवन कठिन हो गया है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पम्प पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं।

टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला वाला ने टैक्स बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना में ट्वीट किया, भयंकर जनलूट- पिछले 13 महीने में पेट्रोल 25.72 रुपये, डीजल 23,93 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ. कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर पार हुआ. पेट्रोल-डीजल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के लिए कच्चे तेल की कीमतें नहीं, मोदी सरकार द्वारा बढ़ाया गया टैक्स जिम्मेदार है।

इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर तंज कसा था। देश में धीमी पड़ गई कोरोना टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। राहुला गांधी ने कहा ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है- कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो!

शिवसेना का तंज- जो ट्विटर कभी भाजपा के लिए आत्मा थी, आज मोदी सरकार के लिए बोझ बन गई

नई दिल्ली । नए आईटी दिशानिर्देशों के बाद केंद्र सराकर और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बीच विवाद जारी है। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सोमवार को अपने संपादकीय में कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भाजपा का राजनीतिक हित खो दिया है और यह सत्ताधारी बीजेपी के लिए एक बोझ बन गया है। शिवसेना ने कहा कि सरकार इसे देश से बाहर फेंकना चाहती है।

संपादकीय में शिवसेना ने कहा है, पहले ट्विटर भाजपा या मोदी सरकार के लिए राजनीतिक संघर्ष या अभियान की आत्मा थी। ट्विटर अब उनके लिए एक बोझ बन गई है। मोदी सरकार यह तय करने की हद तक पहुंच गई है कि इस बोझ को फेंकना है या नहीं। आज, ट्विटर जैसे माध्यमों को छोड़कर देश में सभी मीडिया मोदी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है।÷ संपादकीय का मानना ??है कि ट्विटर ने भाजपा के राजनीतिक हित खो दिए हैं क्योंकि विपक्ष ने उनके कथित झूठे प्रचार का जवाब देना शुरू कर दिया है।

हिंदुस्थानियों (भारतीयों) के लिए ट्विटर कोई जीवनावश्यक वस्तु अथवा आवश्यक सेवा नहीं है। दुनिया के कई देशों में लोग ट्विटर का 'ट' भी नहीं जानते हैं। चीन, उत्तर कोरिया में ट्विटर नहीं है। अब नाइजीरिया ने भी इस सोशल मीडिया को अपने देश से खदेड़ दिया है। ट्विटर को लेकर अब हिंदुस्थान में भी तूफान खड़ा हो गया है। कल तक इस ट्विटर का महत्व भाजपा या मोदी सरकार के लिए उनके राजनीतिक संघर्ष या अभियान की आत्मा थी। ट्विटर अब भाजपा के लिए बोझ बन गया है और इस बोझ को फेंक दिया जाए, ऐसा फैसला करने की हद तक मोदी सरकार पहुंच गई है। देश के सभी मीडिया, प्रचार-प्रसार माध्यम आज मोदी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गए हैं, लेकिन ट्विटर जैसे माध्यम निरंकुश हैं। उस पर मोदी सरकार अथवा भाजपा का नियंत्रण नहीं है। हिंदुस्थान का कानून उन पर लागू नहीं होता। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए सख्त नियम जारी किया है। उन नियमों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई का सामना करें। मोदी सरकार द्वारा ऐसी चेतावनी दिए जाने के बाद भी ट्विटर वाले सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारा कानून और हमारी अदालत अमेरिका में है। आपका भूमि कानून स्वीकार्य नहीं है, ऐसा ट्विटर वाले कहते हैं।

सोशल मीडिया में बीते कुछ वर्षों में कीचड़ उछालने, चरित्र हनन की मुहिम चलाई जा रही है। इसका निर्माण, निर्देशन, रंगमंच, कथा-पटकथा सब कुछ भाजपा के ही हाथ में था। फेसबुक ट्विटर, व्हाट्सएप व अन्य माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल करने की प्रथा अन्य राजनीतिक दल जानते ही नहीं थे, उस समय (2014) भाजपा ने इस कार्य में निपुणता हासिल कर ली थी। उस समय के प्रचार अभियान में भाजपा की फौज धरातल पर कम लेकिन साइबर क्षेत्र में ही ज्यादा शोर मचा रही थी।

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली । भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। मेहुल चोकसी ने कहा है कि आठ से 10 लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा और उसका फोन, घड़ी और बटुआ (वॉलेट) छीन लिया। इन लोगों ने खुद को एंटीगुआ पुलिस से होने का दावा किया था। इन लोगों ने मुझे इतना पीटा कि मैं मुश्किल से होश में रह पाया था। उन्होंने मेरा फोन, घड़ी, वॉलेट छीन लिए थे, लेकिन बाद में यह कहते हुए कि वे मुझे लूटना नहीं चाहते हैं... मेरे पैसे वापस कर दिए थे। एंटीगुआ पुलिस को अपनी शिकायत में मेहुल चोकसी ने कहा है कि बीते एक साल से मैं बारबरा जाबेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर रहा हूं। 23 मई को उसने मुझे अपने घर पर लेने के लिए कहा। जब मैं वहां गया तो सभी दरवाजों से 8-10 लोग आए और मुझे बेरहमी से पीटा। जब मुझे पीटा जा रहा था तो जाबेरिका ने मदद के लिए आवाज भी नहीं लगाई ना तो उसने मेरी सहायता करने की कोशिश की। जाबेरिका ने जिस तरह से व्यवहार किया उससे लगता है कि वह मेरे अपहरण की इस पूरी योजना का हिस्सा थी। उल्लेखनीय है कि पीएनबी को हजारों करोड़ रुपये की चपत लगाकर विदेश भागा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत की पकड़ में आते-आते बच गया था। कैरेबियाई देश डोमिनिका में पकड़े गए चोकसी के खिलाफ सुबूतों का पुलिंदा लेकर एक भारतीय दल चार्टर्ड विमान से वहां पहुंचा था, ताकि उसे भारत लाया जा सके। डोमिनिका की अदालत से चोकसी को भारत लाए जाने से फिलहाल कुछ मोहलत मिल गई है। चोकसी पीएनबी के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अपने भांजे नीरव मोदी के साथ वांछित है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि चोकसी के वकील विपक्षी दलों के साथ मिलकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने में सफल रहे। अदालत ने एंटीगुआ से अवैध तरीके से डोमिनिका में प्रवेश करने की जगह वकीलों की इस दलील को मान लिया कि चोकसी को अगवा कर वहां लाया गया।

कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलने वाली मदद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने पेश की एक्शन टेकन रिपोर्ट

नई दिल्ली । करोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दी जा रही मदद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने इन बच्चों के लिए घोषित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तौर तरीके और प्रक्रिया तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ और वक्त मांगा है। सरकार ने कहा कि इस बारे में सभी स्टेकहोल्डरो के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा, मृत्यु दर का मामला अभी भी केंद्र द्वारा देखा जा रहा है।% उन्होंने यह भी कहा कि कोविड -19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों पर खर्च किए जा रहे पैसे और उनके लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर यूओआई द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि महामारी के दौरान इन अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को सौंपी गई है। केंद्र ने कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को कैसे राहत और वित्तीय सहायता दी जाए, इस पर काम करने के लिए और समय की आवश्यकता है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत सहायता के तंत्र के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श चल रहा है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की। जस्टिस राव ने कहा, हमें केंद्रीय बाल एवं कल्याण मंत्रालय से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मिली है।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऐसे बच्चों के लिए और भी योजनाएं लागू की जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। एमिकस क्यूरी (न्यायालय के मित्र) गौरव अग्रवाल ने मामले में शीर्ष अदालत की सहायता करते हुए कहा कि भारत संघ (श्वद्ध) भी सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और बच्चों की मृत्यु दर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और इस पर भी विचार किया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की कैसे मदद की जाए।

संक्षिप्त समाचार

हज यात्रा को लेकर जल्द घोषणा करेगा सऊदी अरब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने दी जरूरी जानकारी

वॉशिंगटन, एजेंसी । सऊदी अरब के मंत्री माजिद अल-कसाबी ने कहा है कि हज यात्रा को लेकर आने वाले दिनों में जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी. सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का आकलन कर लिया है. रियाद में रविवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सऊदी प्रशासन महामारी से जुड़े हर अपडेट की जानकारी ले रहा है और जल्द ही स्वास्थ्य और हज एवं उमरा मंत्री इस संबंध में घोषणा करेंगे. अल-कसाबी ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट मिलने के कारण ये जरूरी है कि सावधानीपूर्वक और सही तरीके से वायरस के प्रसार से होने वाले नुकसान का मूल्यांकन किया जाए. मंत्री ने कहा, 'हम नहीं चाहते कि इस साल किंगडम या मुस्लिम वर्ल्ड में हज महामारी के प्रसार का केंद्र बने.' हज और उमरा मंत्रालय महामारी की मुश्किल परिस्थितियों के बीच हज और उमर क्षेत्र में दी जाने वाली सेवा में सुधार का काम कर रहे हैं. बीते साल हज और उमरा की मंजूरी एक सुरक्षित मॉडल के विकसित होने के बाद दी गई थी. जिसमें आधुनिक तकनीक पर ध्यान दिया गया. तीर्थयात्रियों तक सुविधा पहुंचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया था.

करोड़ों लोगों को हुआ था फायदा- इस विकसित मॉडल में ईटमारना एप्लीकेशन शामिल है, जिसकी मदद से लोगों को मक्का और मदीना मस्जिद के परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली थी. इससे 2 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा हुआ था. इसके साथ ही मक्का और मदीना के इनाया (केयर) सेंटर द्वारा दी गीई सेवा का लाभ 30 हजार से अधिक लोगों ने उठाया था. मंत्रालय ने लोगों को यातायात से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की गई थीं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. भीड़भाड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की गई थी.

सभी क्षेत्र मिलकर कर रहे हैं काम- अल-कसाबी ने कहा कि सऊदी डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी द्वारा विकसित ईटमारना ऐप आवेदकों के स्वास्थ्य की पुष्टि भी करता है. श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हज और उमरा मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों पवित्र मस्जिद की जनरल प्रेसिडेंसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच निरंतर सहयोग बना हुआ है, ताकि लोग आराम से हज और उमरा कर सकें.'

अमेरिका के फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन पार्टी में गोलीबारी, अब तक तीन लोगों की मौत, कई घायल

वॉशिंगटन, एजेंसी । अमेरिका के फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन पार्टी में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई है और कम से कम छह अन्य घायल हुए हैं. यह मियामी में इस तरह गोलीबारी का नया मामला है . मियामी-डेड पुलिस निदेशक फ्रेडी रामिरेज ने रविवार को बताया कि मृतकों में से एक राज्य सुधार अधिकारी था. उन्होंने कहा कि एक मॉल के लाउंज में पार्टी खत्म होने ही वाली थी कि कुछ गाड़ियां आईं और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी.

सभी मृतकों और घायलों की पहचान तत्काल नहीं बताई गई है. गोलीबारी की घटना उपनगर केंडल में देर रात दो बजे हुई. पुलिस का मानना है कि दो मृतक उस एक कार में थे, जिसमें गोलीबारी करने वाले लोग सवार होकर आए थे. कार की नजदीकी दीवार से टक्कर हो गई थी. अधिकारियों को कार में से एक बंदूक मिली है लेकिन गोलीबारी से इसका स्टीक संबंध अभी साफ नहीं है. मियामी में हाल फिलहाल में गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं.

मृतकों में एक महिला शामिल- पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल है. जबकि जो छह अन्य लोग घायल हुए हैं, उनमें तीन पुरुष और तीन महिलाएं हैं. इन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. मृतक महिला की पहचान फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन ऑफिसर टेलिशा टेलर के तौर पर हुई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है. इसे लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया है और टेलर के परिवार एवं दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं- पुलिस ने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई है. अधिकारी ने कहा कि इस तरह की हिंसा को अब रुक जाना चाहिए. हर वीकेंड पर ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं. गौरतलब है कि अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिलती हैं. करीब एक हफ्ते पहले ही कैलिफोर्निया के रेल यार्ड में एक कर्मचारी ने गोलीबारी कर दी थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी.

लाल ग्रह पर इंजेंविनिटी हेलीकॉप्टर की 7वीं उड़ान, जानें क्या है इसकी खासियत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजेंविनिटी हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर लाल ग्रह पर उड़ान भरी। इंजेंविनिटी को चलाने वाले लोग इस 1.8 किलोग्राम वजनी हेलिकॉप्टर को 7वीं बार मंगल के आसमान में उड़ाया गया। नासा की योजना के मुताबिक इस हेलिकॉप्टर को एक नए एयरफील्ड में भेजने की है। इंजेंविनिटी को जेजेरो क्रेटर की सतह की वर्तमान लोकेशन से दक्षिण में 105 मीटर दूर ले जाने की योजना बनाई गई है। नासा के अधिकारियों ने कहा है कि उड़ान के बाद के तीन दिनों में इसका डाटा पृथ्वी पर भेजा जाएगा। यह दूसरी बार होगा, जब इंजेंविनिटी हेलीकॉप्टर किसी ऐसे हवाई क्षेत्र में उतरेगा, जहां उसने पिछली उड़ान के दौरान हवा से सर्वेक्षण नहीं किया था। इसके बजाय इंजेंविनिटी नासा के 'मार्स रिकोनिसेंस ऑर्बिटर' पर लगाए गए कैमरे द्वारा एकत्र की गई तस्वीर पर भरोसा कर रही है। ऑपरेशन के लिए यह नया बेस अपेक्षाकृत सपाट है। यहां थोड़े बहुत ही अवरोधक हैं।

इसके पूर्व उड़ान के दौरान हुई थी गड़बड़ी- इसके पूर्व इंजेंविनिटी ने 22 मई को अपनी छठी उड़ान के दौरान भी एक नई जगह पर उड़ान भरी थी। हालांकि, यह उड़ान सफल नहीं हो पाई थी। दरअसल, हेलिकॉप्टर में एक गड़बड़ी आ गई थी, इस वजह से इस पर लगे नेविगेशन कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर में थोड़ी देर के लिए बाधा आ गई, लेकिन हेलिकॉप्टर सफलतापूर्वक अपने निर्धारित लैंडिंग वाली जगह पर लैंड करने में कामयाब हुआ था।

मिशन पर 2.7 अरब डॉलर का खर्च- बता दें कि पर्सिवियरेंस रोवर 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था। 2.7 अरब डॉलर का यह मिशन है। इसका प्राथमिक मकसद करीब तीन अरब साल पहले जब मंगल जीवन के ज्यादा अनुकूल था तब शायद मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव पनपें हों इसका पता लगाना है। रोवर में दो माइक्रोफोन हैं। पिछले दिनों उसने इसकी मदद से सतह पर चहलकदमी का आडियो भेजा था। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक 16 मिनट का ऑडियो जारी किया था। इसमें मंगल की सतह पर रोवर के पहियों के चलने की आवाज सुनाई दे रही है।

नए शांति मिशन पर काबुल में खलीलजाद, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने की मुलाकात

काबुल । अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने काबुल पहुंचे अमेरिका के अंतर मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त वाशिंगटन के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय के अनुसार, रविवार को दोनों पक्षों की मुलाकात के दौरान सहयोग बढ़ाने व द्विपक्षीय राजनीतिक, सुरक्षा व आर्थिक संबंधों को बनाए रखने समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई।

11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर किए गए राष्ट्रपति जो बाइडन के ऐलान के एक माह बाद खलीलजाद अफगानिस्तान पहुंचे हैं। टोलो न्यूज के अनुसार अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए यह ऐलान किया गया है। पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेनाओं की एक तिहाई वापसी हो चुकी है। अमेरिकी सैन्य बल की ओर से अफगान सैन्य बल को कुछ बेस सौंप दिए गए। अफगानिस्तान में हिंसा चरम पर है जबकि दोहा में जारी शांति वार्ता में कोई प्रगति नहीं है। खलीलजाद के इस दौरे से पहले अमेरिका के गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की ओर से अफगानिस्तान के विकास व राजनीतिक समझौते के क्रम में अमेरिका की ओर से सहायता जारी रखा जाएगा जिससे युद्ध का अंत हो सकेगा। गनी के अलावा खलीलजाद ने रविवार को शांति प्रक्रिया के उच्चायोग के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मुलाकात की।

चीन ने दुनिया से छिपाया! वायरस के महामारी घोषित होने से पहले ही मशहूर वैज्ञानिक ने कोविड वैक्सीन के लिए फाइल किया पेटेंट, फिर अचानक हुई मौत

बीजिंग एजेंसी । कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से निकलने की बात आए दिन नई-नई रिपोर्ट्स में की जा रही है. अब खबर आई है कि चीनी सेना के एक वैज्ञानिक ने बीमारी के वैश्विक महामारी घोषित होने से काफी पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पेटेंट फाइल कर दिया था . वैज्ञानिक युसेन झोउ चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के लिए काम करते थे. डेली मेल ने एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार के हवाले से कहा है कि झोउ ने चीनी राजनीतिक पार्टी की ओर से 24 फरवरी, 2020 में कागजी कार्रवाई की थी. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को 11 मार्च, 2020 में महामारी घोषित किया था.

झोउ ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ भी काफी निकटता से काम किया है. जिनमें बैट वुमन शी झेंगली शामिल है. वह इस लैब की डिप्टी डायरेक्टर हैं और चमगादड़ों में कोरोना वायरस की जांच किए जाने को लेकर दुनियाभर में जानी जाती हैं. झोउ के लैब से संबंध के चलते उस दावे को और बल मिल रहा है, जिसमें वुहान लैब से वायरस लीक होने की बात कही जा रही है. ये भी कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से पहले ही चीन को पता चल गया था कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है.

हालांकि एक बात ये भी हैरान करने वाली है कि पेटेंट फाइल करने के तीन महीने से भी कम समय बाद झोउ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वैज्ञानिक की मौत की बात चीन ने छिपाई है, वहां की केवल एक ही मीडिया रिपोर्ट में वैज्ञानिक की मौत की जानकारी दी गई है.

हैरानी इस बात की भी है कि वह देश के नामी वैज्ञानिक थे. अखबार ने बताया कि झोउ ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर सहित अमेरिकी संस्थानों से जुड़े शोध पर भी काम किया था. हाल के हफ्तों में दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों ने इस जांच पर जोर दिया है कि वायरस वुहान लैब से ही निकला है या नहीं.

अमेरिका ने दिए जांच के आदेश

चीन लैब लीक थ्योरी को बार-बार खारिज कर रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते हफ्ते खुफिया एजेंसियों को वायरस की उत्पत्ति की जांच करने को कहा था. जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि वायरस को किसी इंसान ने तो नहीं बनाया है. इसके लिए 90 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. अमेरिका में होने वाली इस जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि कहीं चीन ने लैब लीक थ्योरी को छिपाने की कोशिश तो नहीं की है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड को लेकर हमेशा से ही चीन पर आरोप लगाते रहे हैं, उन्होंने हाल ही में इसे 'वुहान वायरस' कहते हुए कहा था कि चीन को दुनियाभर में मचाई तबाही के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए.

हूथी विद्रोहियों ने कहा किंग खालिद एयरबेस पर सटीक ड्रोन हमला, सऊदी अरब बोला- विफल किया

सना । यमन के हूथी विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के किंग खालिद एयर बेस पर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया है। ये हवाई अड्डा शामिस मुशेत शहर के दक्षिण में स्थित है। हूथी विद्रोहियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये हमला एक दम सटीक निशाने पर किया गया है। विद्रोहियों के प्रवक्ता येहया सरेआ ने ये बयान रविवार को हूथियों द्वारा चलाए जा रहे टीवी नेटवर्क अल मसीरहा पर दिया है। हालांकि शिन्हुओ न्यूज एजेंसी ने सऊदी अरब के टीवी नेटवर्क अल अरेबिया के रिपोर्टर के हवाले से बताया है कि सऊदी और उनके सहयोगियों ने इस ड्रोन का हमले से पूर्व ही पता लगा लिया था और इसको समय रहते मार गिराया गया। उन्होंने कहा है कि ये हमला रविवार की सुबह खामिस मुशेत की तरफ किया गया था।

हूथियों की तरफ से ये हमला ओमारी हाई लेवल डेलिगेशन के यमन की राजधानी सना पहुंचने के एक दिन बाद किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर इस डेलिगेशन के जरिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोनों पक्षों के बीच सीजफायर कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए हूथियों से भी हथियार डालने और सीजफायर करने की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सऊदी के समर्थन वाली यमन सरकार के तेल से भरे प्रांत मारिब पर हमला कर उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था।

महिलाओं की टॉयलेट से संबंधित समस्या का ब्रिटेन में निकला हल, छात्रों ने डिजाइन किया खास तरह का टॉयलेट

लंदन, एजेंसी । ब्रिटेन के छात्रों ने महिलाओं के लिए एक खास तरह का टॉयलेट बनाया है, जिसकी दुनियाभर में तारीफ की जा रही है. ये अनूठा टॉयलेट दो छात्रों ने डिजाइन किया है. छात्रों ने अपने मास्टर्स के एक प्रोजेक्ट में महिलाओं से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामियाबी भी मिली है. इन छात्रों का नाम एंबर प्रोबिन और हेजल मैकशेन है. इन्होंने दावा किया है कि इनका बनाया हुआ लेडीज टॉयलेट पूरी तरह से हैंड फ्री है.

इसके साथ ही ये पुरानी तरह के लेडीज टॉयलेट से छह गुना अधिक साफ, सुरक्षित और प्रभावशाली है. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों को टॉयलेट बनाने का ये आइडिया एक म्यूजिक फेस्ट से आया था. एंबर और हेजल ने इसके लिए काफी रिसर्च की. फिर जब इन्होंने शहर में आयोजित हुए एक म्यूजिक फेस्ट की तस्वीरों को देखा तो इन्हें काफी कुछ नया सोचने में मदद मिली. इस फेस्ट में हर साल हजारों की संख्या में महिलाएं भी आती हैं. लेकिन उनके लिए बेहतर और साफ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती.

34 फीसदी लंबी होती है महिलाओं की लाइन-महिलाओं की इसी परेशानी पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि सार्वजनिक स्थानों में पुरुषों के लिए अधिक टॉयलेट हैं, जबकि महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ये लाइन पुरुषों की तुलना में 34 फीसदी तक लंबी होती है. आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के औसतन 10 टॉयलेट के बीच महिलाओं के लिए महज एक टॉयलेट होता है . जिसके कारण महिलाएं गंदगी का शिकार हो जाती हैं और उनके बीमारी से ग्रसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है. मंथली पीरियड में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है.

नए टॉयलेट में वायरस का खतरा बिल्कुल नहीं- एंबर और हेजल ने इसी समस्या का हर खोज निकाला है. इनका कहना है कि लॉक होने वाला टॉयलेट ज्यादा खतरनाक होता है, इससे वायरस का खतरा बढ़ता है और समय भी अधिक लगता है . लेकिन इनके डिजाइन किए गए टॉयलेट में हैंडल को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बाहर से किसी पुरुष या महिला के शरीर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है. फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है. छात्रों का कहना है कि ऐसा करके इनका मकसद टॉयलेट को लेकर कोई क्रांति लाना नहीं है.

तो क्या हज पर नहीं जा पाएंगे पाकिस्तान के लोग? चीन की वजह से खड़ी हो सकती है बड़ी मुसीबत

इस्लामाबाद , एजेंसी । पाकिस्तान को चीन से 'दोस्ती' एक बार फिर से भारी पड़ सकती है. कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन पर भरोसा जताया. यहां तक कि चीन के साथ मिलकर स्वदेशी वैक्सीन PakVac भी बनाई. मगर सऊदी अरब समेत कई देशों ने चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है. इस वजह से पाकिस्तानियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है.

सऊदी अरब चीनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट स्वीकार ही नहीं कर रहा है. इस कारण हज या बिजनेस या फिर नौकरी की तलाश में सऊदी जाने वाले पाकिस्तानियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद उन देशों से बात करने में लगे हैं, जिन्होंने चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है.

सऊदी ने दी इन वैक्सीन को मंजूरी- डब्ल्यूएचओ चीन की दो वैक्सीन सिनोफार्मा और सिनोवैक को मान्यता दे चुका है. मगर सऊदी अरब ने चीन में बनी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है. उसने अब तक फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन को ही मंजूरी दी है. पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने पाकिस्तान में सऊदी के राजदूत नवाफ बिन सईद अहमद अल-मालकी से मुलाकात की थी. उन्होंने चीनी वैक्सीन को भी अपनी लिस्ट में जोड़ने का आग्रह किया.

फाइजर की वैक्सीन को प्राथमिकता- बीबीसी की एक खबर के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री असद उमर ने कहा था कि जो लोग हज करना चाहते हैं या नौकरी, पढ़ाई के लिए उन देशों में जाना चाहते हैं, जहां चीनी वैक्सीन को मान्यता नहीं है, उन्हें फाइजर की वैक्सीन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. लेकिन साथ ही कहा कि अगर देश अपनी पसंद के ब्रांड को प्राथमिकता देंगे, तो यह एक वैश्विक समस्या बन जाएगी.

चीन की वैक्सीन पर सवाल क्यों- पूरी दुनिया को कोरोना देने वाले चीन की वैक्सीन की विश्वसनीयता पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं. वॉल स्ट्रीट जनरल की एक खबर के अनुसार बहरीन में चीनी वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी संक्रमण के काफी मामले देखने को मिल हैं. जोखिम को देखते हुए यहां लोगों को फाइजर की वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में दी गई.

चीनः दो सप्ताह में तीसरा घातक हमला, चाकू से 6 नागरिकों की हत्या; 14 जख्मी

बीजिंग । पूर्वी चीन में घातक हमले का मामला सामने आया है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। मामले की जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी। चीन में इसी तरह के हमले पहले भी हुए हैं लेकिन ऐसे हमलावरों को मानसिक रूप से बीमार या समाज के प्रति विद्वेष रखने वाला करार दिया गया।

शनिवार को हुई इस घटना के हमलावर की पहचान वु के तौर पर की गई है। घरेलू मामलों से परेशान 25 वर्षीय शख्स वु हुएनिंग काउंटी निवासी है। इंटरनेट पर इस मामले का वीडियो वायरल हो गया। पिछले दो सप्ताह में इस तरह का ये तीसरा हमला है।

चीन के कानून के तहत आग्नेय शस्त्रों की बिक्री और उन्हें रखने पर पाबंदी है और आमतौर पर बड़े हमले चाकू या देसी विस्फोटकों से होते हैं। अंक्रिंग जिला पुलिस थाने ने चीनी सोशल मीडिया मंच वेइबो पर जारी बयान में बताया कि अन्हुई प्रांत की अंक्रिंग शहर के अधिकारियों को शनिवार दोपहर खबर मिली कि एक व्यक्ति ने सड़क पर पैदल चल रहे लोगों पर चाकू से हमला किया।

पुलिस ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक, अंक्रिंग के ब्लड बैंक ने लोगों से रक्त दान करने की अपील करते हुए कहा कि ब्लड बैंक में जमा खून अपर्याप्त है। पिछले साल दिसंबर में पूर्वोत्तर चीन में सौना और बाथहाउस के बाहर चाकू से हुए हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हुई थी और इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए थे। इससे पहले 22 मई को लोगों की भीड़ में कार घुसा दी गई इसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार हमलावर लियू का कहना है कि वह सोसायटी से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसका एक इंवेस्टमेंट फेल हो गया था।

अफ्रीका में आतंक मचाने वाले बोको हराम लीडर अबुबकर ने खुद को बम से उड़ाया, 300 स्कूली लड़कियों को किडनैप कर आया था चर्चा में

वॉशिंगटन, एजेंसी । खूंखार संगठन बोको हराम के लीडर अबुबकर शेकऊ ने आत्महत्या कर ली है. उसने दुश्मन संगठन इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के जिहादी लड़ाकों के साथ लड़ाई के दौरान खुद को बम से उड़ा लिया. इससे करीब दो हफ्ते पहले भी शेकऊ की मौत की खबर आई थी लेकिन तब इसकी पुष्टी नहीं हो सकी थी. लेकिन इस बार इस्लामिक स्टेट ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है.

इसमें आईएसडब्लूएपी का नेता अबू मुसाब अल-बारनवी को कहते सुना जा सकता है, 'शेकऊ ने धरती पर अपमानित होने के बजाय इसके बाद अपमानित होना बेहतर समझा है. उसने खुद को विस्फोट से उड़ाकर मार लिया है.' ये ऑडियो एएफपी को उसी सूत्र से मिला है, जो पहले से समूह से संबंधित जानकारी देता रहा है. हालांकि बोको हराम ने अभी तक शेकऊ की मौत की पुष्टि नहीं की है. बोको हराम ने नाइजीरिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में काफी आतंक मचाया है और बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की हैं.

जंगल में भेजे गए लड़ाके- नाइजीरिया की सेना का कहना है कि वह इस इस मामले में अभी जांच कर रही है. ऑडियो में आईएसडब्लूएपी ने बताया है कि कैसे संबीसा के जंगलों में बोको हराम के ठिकाने तक लड़ाके भेजे गए. उस वक्त शेकऊ अपने घर में बैठा हुआ था. वह वहां से भागता रहा और इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उसे ढूंढते रहे. जब वह झाड़ियों में छिपा मिला तो उससे और उसके साथियों से कहा गया कि वह पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन शेकऊ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और खुद को बम से उड़ा लिया. बता दें बोको हराम की स्थापना साल 2002 में मोहम्मद यूसुफ ने की थी. इसने 2009 में इस्लामिक देश की स्थापना करने के लिए हिंसक गतिविधियां करना शुरू कर दिया. अमेरिका ने 2013 में बोको हराम को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था.

बड़ी संख्या में किए अपहरण- अबुबकर शेकऊ तब खबरों में आया था, जब 2014 में उसने एक साथ करीब 300 लड़कियों को उनके स्कूल से अगवा कर लिया था. उसे कई बार मृत घोषित किया जा चुका है लेकिन मौत की पुष्टि होने की बात अब की गई है. देश की सेना भी इस खूंखार संगठन से निपटने के लिए इसके ठिकानों पर हवाई हमले करती है. इससे जुड़े कई लोगों को भी अब तक पकड़ा जा चुका है. बोको हराम की शुरुआत से लेकर अभी तक 40 हजार से अधिक लोगों को मारा जा चुका है. इसके आतंक से बचने के लिए 20 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.

पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा, सिंध में दो ट्रेनें टकराईं; 36 लोगों की मौत-50 घायल

कराची, एजेंसियां । पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज सुबह-सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत इलाके में दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। इस रेल हादसे में 50 लोग घायल हुए हुए हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में सोमवार को दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई।

रेडियो पाकिस्तान ने रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया कि सर सैयद एक्सप्रेस, घोटकी शहर के पास रायती और ओबरो रेलवे स्टेशनों के बीच मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। अधिकारियों को आशंका है कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस टक्कर में फिलहाल तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव और राहत कार्य जारी है। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार, लगभग 13 से 14 ट्रेन कारें पटरी से उतर गईं, जबकि छह से आठ पूरी तरह से नष्ट हो गईं। ट्रेनों में फंसे यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. घटना के बाद से ट्रैक के सभी किनारों को बंद कर दिया गया है।

कैसे हुआ हादसा - यह हादसा घोटकी के पास हुआ है। जियो टीवी के मुताबिक, मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां अनियंत्रित होकर दूसरी ट्रैक पर जा गिरीं और सामने से आ रही सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई. इस कारण बोगियों के टुकड़े हो गए। मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतर गई।

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा तड़के 3 बजकर 45 मिनट पर हुआ है। हादसे के चार घंटे बीत जाने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही हेवी मशीनरी अभी तक यहां पहुंचाई गई है। अभी भी कई यात्री बुरी तरह फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई यात्री ऐसे फंसे हैं जिन्हें ट्रेन काटकर ही वहां से निकाला जा सकता है। बताया जा रहा है कि घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ले जाया जा रहा है।

अमेरिकी मार्शल टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा विंस्टन बूगी स्मिथ जूनियर द्वारा गुरुवार को घातक शूटिंग पर लोगों ने मिनियापोलिस में मार्च किया।

चीन में कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों के बाद सख्त पाबंदियां, यात्रा और आवाजाही पर लगा प्रतिबंध

बीजिंग । चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। चीन के ग्वांगझोउ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां लोगों की यात्रा और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें रद कर दी गई हैं। चीन के ग्वांगझोउ में अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे तब तक शहर न छोड़ें जब तक

कि देश मे कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों के बीच उनकी यात्रा

बिल्कुल आवश्यक ना हो। रिपोर्ट के अनुसार, कोविड -19 नियंत्रण और रोकथाम पर शहर के मुख्यालय ने ये भी कहा कि सोमवार से ग्वांगझोउ छोड़ने वालों को यात्रा करने से पहले 48 घंटे के अंदर नेगेटिव न्यूक्लिक एसिड परीक्षण परिणाम देना होगा।

ग्वांगझू शहर में शनिवार को कोरोना के सात स्थानीय रूप से प्रसारित मामले और तीन स्थानीय रूप से प्रसारित बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण दर्ज किए गए। इसके साथ ही यहां बाहर से आए 7 कोरोना के मामले भी सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार, बाहरी देशों से आए सभी मामले बांग्लादेश, कंबोडिया, फ्रांस, कनाडा, कैमरून और भारत से ग्वांगडोंग में आए हैं। 21 मई को ग्वांगझू शहर में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद ने अब तक कुल 94 नए वायरस संक्रमणों की सूचना है, जिसमें 80 कोरोना के पुष्ट मामले शामिल हैं।

दिसंबर 2019 में हुबेई प्रांत के वुहान शहर में कोरोना महामारी का पहला मामला सामने आने के बाद से चीन में अब तक कुल 91,248 कोरोना वायरस मामले और 4,636 मौतें हुई हैं।

चीन पर बढ़ रहा दबाव- चीन ने कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने की आधिकारिक घोषणा दिसंबर, 2019 में की गई थी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का सच पता लगाने के लिए चीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका से लेकर कई वैज्ञानिकों द्वारा इसका सच सामने लाने और इसकी जांच का दबाव चीन पर लगातार बढ़ रहा है।

मेट्रो के अंदर उड़ी नियमों की धज्जियां, कोच में खड़े होकर सफर करते नजर आए दर्जनों लोग

नई दिल्ली । दिल्ली अनलाक होते ही सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित किए गए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। चाहे मेट्रो हो या बाजार, सभी जगह नियम टूटते ही दिखाई दिए। व्यस्त बाजारों में तो लोग उमड़ पड़े, सड़कों पर जाम लग गया। मेट्रो में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। मेट्रो ने पहले ही ऐलान किया था कि मेट्रो में लोग खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक सीट छोड़कर ही सफर करेंगे मगर ये सारे नियम टूटते हुए दिखे। मेट्रो के हर कोच में लोग खड़े होकर सफर करते देखे गए।

दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के कारण परिचालन बंद होने के करीब एक माह बाद सोमवार से दिल्ली मेट्रो वापस पटरी पर लौटी। दिल्ली मेट्रो के सभी 10 लाइनों पर मेट्रो रफ्तार से चली, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर क्षमता से 50 फीसद कम यात्रियों के साथ ही परिचालन को मंजूरी दी गई थी। मेट्रो कोच में सिर्फ बैठकर सफर करने की व्यवस्था की घोषणा पहले ही की गई थी, इसके साथ लोगों को एक सीट छोड़कर बैठना था मगर ये सारे नियम धरे के धरे रह गए। ये भी तय किया गया था कोई भी यात्री खड़ा होकर कतई सफर नहीं करेगा मगर भीड़ में ये सब बेमानी हो गए। सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, एक मेट्रो कोच में करीब 300 यात्री सफर करते हैं प्रत्येक कोच में करीब 50 सीट है। अब एक कोच में 25 यात्री ही सफर कर पाएंगे। इस तरह आठ कोच की मेट्रो में करीब 200 व छह कोच की मेट्रो में करीब 150 यात्री सफर कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 348 किलोमीटर है और 253 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर कुल 682 गेट हैं, जिसमें से करीब 260 गेट ही खुलेंगे। प्रत्येक स्टेशन पर सिर्फ एक गेट खुला होगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार शुरुआती दो दिन स्टेशनों पर मेट्रो पांच से 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध कराई जा रही है जो सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना अधिक है। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 330 मेट्रो ट्रेनें हैं। 10 फीसद ट्रेनें रिजर्व में रहती हैं। सामान्य दिनों में करीब 300 मेट्रो ट्रेनों का परिचालन होता है, लेकिन अभी करीब 150 मेट्रो ट्रेनें ही ट्रैक पर उतरेंगी, जो करीब ढाई हजार फेरे लगाएंगी। डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा कि बुधवार से मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। 10 मई से दिल्ली मेट्रो का परिचालन बंद है। पिछले साल कोरोना का संक्रमण शुरू होने पर भी करीब साढ़े पांच माह मेट्रो का परिचालन बंद था।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के काफिले को नई दिल्ली के अक्षरधाम में ड्राइव-इन टीकाकरण केंद्र पर रोकने की कोशिश करते हुए।

संक्षिप्त खबर

रेड लाइट जंप करना पड़ेगा महंगा, 3 महीने के लिए निरस्त होगा लाइसेंस

नोएडा । रेड लाइट होने के बावजूद वाहन को दाएं-बाएं से निकलने का प्रयास अब भारी पड़ सकता है। गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब सख्ती बरतने जा रही है। इस नियम के उल्लंघन पर तीन माह के लिए डीएल निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। सोमवार से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि रेड लाइट आन होने के बावजूद कुछ लापरवाह चालक आड़े-तिरछे से गाड़ी पास करने की कोशिश करते हैं, जबकि व्यस्त चौक होने से ही यहां ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, ताकि वाहन आसानी से पास हो सकें। अब इस लापरवाही पर सीधा चालक का डीएल जब्त होगा। तीन माह तक लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। कार्रवाई से रेड लाइट जंप करने पर हो रहे हादसों में भी कमी आएगी। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति ड्रंक एंड ड्राइविंग, मोबाइल उपयोग और ओवर स्पीडिंग के नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर दिन में बंदिशों से छूट मिली है। यातायात पुलिस ने आटो, ई-रिक्शा, बस समेत अन्य सार्वजनिक वाहन में सवारियां तय कर दी हैं। सिग्नल पर रुकने के दौरान शारीरिक दूरी बनाने का प्रयास किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि आटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ बैठक में निर्देशित किया गया कि ऑटो में दो और ई-रिक्शा में तीन से अधिक सवारी नहीं बैठाई जाएं। वहीं चार पहिया वाहन चार सवारियां ही बैठाई जा सकेगी। यातायात नियम का पालन कराने के लिए 125 स्थान तय किए गए हैं। इन चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस सख्ती से शारीरिक दूरी का पालन कराएगी। सार्वजनिक वाहन में तय से अधिक सवारी बैठाने पर कार्रवाई होगी।

उमर खालिद और खालिद सैफी गैंगस्टर नहीं हैं, कोर्ट ने खारिज की हथकड़ी लगाकर पेश करने की याचिका

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि वे गैंगस्टर नहीं हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की गई इस याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों खालिद और सैफी को पीछे की ओर से दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने की अनुमति मांगी गई थी. याचिका में कहा गया कि वे उच्च जोखिम वाले कैदी हैं. न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसे आधार रहित करार दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस और जेल प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों ने बिना प्रक्रिया अपनाए और दिमाग लगाए यह आवेदन दाखिल किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बीते 5 जून को जारी आदेश में कहा, ''जिन आरोपियों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर पेश करने की अनुमति मांगी गई, वे पुराने किसी मामले में दोषी करार नहीं दिए गए हैं. वे गैंगस्टर भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस समय इस याचिका की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कोविड-19 के चलते आरोपियों को भौतिक रूप से अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है. आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी के ऊपर कैद से भागने की आशंका जाहिर करते हुए अदालत में उन्हें हथकड़ी लगाकर पेश करने की इजाजत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी, उस समय दिल्ली पुलिस की ओर से डीसीपी मौजूद थे, जिन्हें अदालत ने यह निर्देश दिया.

एम्स दिल्ली में बच्चों पर कोवैक्सिन के ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू, जांच रिपोर्ट आने पर लगेगी वैक्सीन

नई दिल्ली । कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन के टीके के बच्चों में परीक्षण के लिए जांच शुरू हो गई. यहां के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार से दो वर्ष के बच्चे से 18 साल तक के किशोर की जांच शुरू की गई. वहीं, पटना स्थित एम्स में बच्चों में यह पता लगाने के लिए परीक्षण शुरू हो गया है कि क्या भारत बायोटेक के टीके बच्चों के लिए ठीक हैं ? जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों को टीके लगाए जाएंगे. यह परीक्षण 525 स्वस्थ बच्चों पर किया जाएगा जिसके तहत बच्चों को टीके की दो खुराकें दी जाएगीं. इनमें से पहली खुराक के 28वें दिन दूसरी खुराक दी जाएगी. एम्स के 'सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन' के प्रोफेसर डॉ संजय राय ने कहा,'' कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए बच्चों की जांच शुरू कर दी गई है. और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों को टीके की खुराक दी जाएगी.'' भारत के दवा नियामक ने कोवैक्सीन का दो साल के बच्चे से ले कर 18 साल की उम्र के किशोरों पर परीक्षण करने की मंजूरी 12 मई को दे दी थी. देश में टीकाकरण अभियान में वयस्कों को कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं. वहीं, कल खबर सामने आई थी कि दिल्ली सरकार ने रविवार को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्देश दिया कि 18-44 साल आयु वर्ग में जून के महीने या अगले आदेश तक कोवैक्सीन सिर्फ सेकेंड डोज लेने वालों को लगाएं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्वास्थ्य और राजस्व विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए निर्देश देता है कि कोवैक्सिन के लिए कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम यह सुनिश्चित करेंगे कि जून या अगले आदेश तक कोवैक्सिन का उपयोग केवल उन लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा, जो इस दौरान टीकाकरण की दूसरी डोज लेने के पात्र हैं.

भाजपा ने आप सरकार से पूछा-दिल्ली में कब लागू होगी वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना?

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को केंद्र सरकार की ओर से खारिज करने के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र और भाजपा दोनों पर पूरी तरीके से हमलावर है. दूसरी ओर, भाजपा ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. और कहा है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है. भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष एवं रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में ई-पॉस लागू किया गया है. परंतु दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा ई-पॉस व्यवस्था लागू करने के बाद इसे समाप्त करना भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ई-पॉस व्यवस्था अर्थात वन नेशन-वन राशन कार्ड देशभर में लागू की गई है.

दिल्ली में लोग अपने घर के नजदीक लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन, पोलिंग बूथ पर होगा टीकाकरण

(बिरेन्द्र कुमार शर्मा)

नई दिल्ली । कोरोना रोधी टीकाकरण सफल बनाने की कड़ी में दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत दिल्ली में लोग सोमवार से अपने घर के नजदीक बने पोलिंग बूथ पर कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत सोमवार से की जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में सोमवार से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का नाम है- जहां वोट वहां वैक्सीन। इसके तहत लोग अपने घर के नजदीक पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह अभियान 45 वर्ष से अधिक ऊपर उम्र वालों के लिए है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 45 से ऊपर से 57 लाख लोग दिल्ली में हैं। अब तक 27 लाख लोगों को पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 30 लाख लोगों को अभी कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में टीकाकर को सफल बनाने के लिए लोगों से घर घर जाकर कहा जाएगा कि जहां वोट डालने जा रहे हो वहां वैक्सीन लगेगी। सोमवार से दिल्ली में 70 वार्ड में अभियान शुरू हुआ है। दिल्ली में 280 वार्ड हैं। हर सप्ताह 70 -79 वार्ड में अभियान चलेगा। बीएलओ घर घर जाएंगे और स्लाट देकर आएंगे। उसी दिन लोगों को जाना होगा। जो लोग नहीं जाएंगे उनके घर बीएलओ दोबारा जाएंगे। घरों से लोगों को ई-रिक्शा से उन्हें वैक्सीन सेंठर तक लाया जाएगा।

जहां वोट वहां वैक्सीन% अभियान 5 दिन तक चलेगा, ताकि पूरा बूथ कवर हो सके। इसके साथ ही सभी 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग सके, इसकी भी कोशिश रहेगी। इसके बाद 4 हफ्ते में हम कह पाएंगे कि 45 साल के ऊपर के लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है। फिर 3 महीने बाद यही अभियान चलायेंगे, ताकि उनकी दूसरी वैक्सीन लग सके। सबसे अपील है बूथ लेव आफिसर की टीम आपके घर आएगी, उन्हें सहयोग करें, आप बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं।

केजरीवाल सरकार पर कांग्रेस ने लगाये आरोप, कहा-डोर स्टैप राशन डिलीवरी पर जनता को करती रही है गुमराह

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी में इस मामले पर केजरीवाल सरकार और भाजपा का तंज कसा है. कांग्रेस ने कहा है कि एक तरफ जहां देश कोरोना संक्रमण से युद्ध लड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल-भाजपा आपस में लड़ रहे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाते हुये कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ मिलकर 'घर-घर राशन योजना' का इस्तेमाल समय-समय पर दिल्लीवासियों को गुमराह करने के लिए करते रहे हैं.

उन्होंने कहा कि केजरीवाल व भाजपा की सरकार कोरोना काल में लोगों को राहत व टीके देने में विफल रही है. कोरोना योद्धाओं को सम्मान नहीं दिया है. अब दोनों सरकारें पुनः मूल मुद्दे से भटकाने के लिए नूरा-कुश्ती कर रही हैं.

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून बना गरीबों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया. लेकिन यह बेहद चिंता की बात है कि भाजपा व अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिये गए अधिकारों को गरीब जनता तक पहुँचाने की जगह क्रेडिट लेने के लिए गंदी राजनीति कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार के दौरान दिल्ली में 31 लाख राशन कार्ड थे जो अब घटकर 17 लाख राशन कार्ड हो गए है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 463 राशन की दुकानों को बंद कर 420 से अधिक नए शराब के ठेके खोले.

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार की अगर मंशा लोगों को राशन पहुंचाने की होती तो राज्य स्तर पर जिन लगभग 54 लाख लाभार्थी के राशन कार्ड आवेदन पिछले 7 वर्षों से पेंडिंग हैं. उन्हें राज्य स्तर पर योजना बना राशन मुहैया कर सकते थे. उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गयी अन्न श्री योजना के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सीधे खाते में राशि ट्रांसफर करने का काम करती थी. लेकिन केजरीवाल सरकार ने न तो कोई नया राशन कार्ड बनाया ओर न ही कोई योजना बनायी जिससे गरीबों को राशन मुहैया कराया जा सके.

ब्रिटिश नागरिकों को कर चोरी का भय दिखाकर की जाती थी ठगी, 21 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली । नारायणा इलाके में चल रहे एक काल सेंटर से ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को टैक्स व कस्टम आडिट की बात कहकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। इनके कामकाज के तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना ये लोग वहां के सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। आलम यह है कि इस मामले में ब्रिटिश उच्चायोग से भी दिल्ली पुलिस ने संपर्क कर इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में जांच कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर नारायणा थाना पुलिस ने इस काल सेंटर का पता लगाया और यहां काम करने वाले 21 लोगों को दबोच लिया। यहां जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें काल सेंटर संचालक अच्छी खासी तनख्वाह देते थे।

उन कर्मियों को तनख्वाह के अलावा भी पैसा दिया जाता था जो अधिक से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। गिरफ्तार आरोपितों में सागरिका, बाला, योगेंद्र, मुदित, मानव, राजू कौशतभ, अजय, आशुतोष, निखिल, राहुल, जतिन, इशान, अभिषेक, केशव, धर्मेश, अंकित, आशिक, आशीष, हर्षित, रोहन, योगेश शामिल है। इनमें सागरिका व बाला के जिम्मे पूरे फ्लोर को संभालने की जिम्मेदारी थी। अभी इस मामले में मुख्य आरोपित फरार है जिसकी तलाश में छापेमारी चल रही है।

पुलिस के अनुसार यह फर्जी काल सेंटर नारायणा गांव के पास चलाया जा रहा था। नारायणा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर समीर श्रीवास्तव के नेतृत्व व एसीपी विजय सिंह की देखरेख में काल सेंटर का पता लगते ही पुलिस ने यहां छापा मारा। पुलिस ने मौके पर पाया कि यहां गैर कानूनी तौर से इंटरनेट काल का इस्तेमाल कर ग्रेट ब्रिटेन के लोगों से संपर्क किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार यहां प्रतिदिन सुबह के समय ये लोग एक साथ करीब 50 हजार लोगों को इंटरनेट पर संदेश भेजकर उनसे कर चोरी व कस्टम जांच में गड़बड़ी को लेकर जुर्माना लगाने की बात कहते थे। यह संदेश भले ही भारत से भेजे जाते थे लेकिन वहां की वेबसाइट को ये कुछ देर के लिए हैक कर लेते जिससे कि वहां जब लोगों को यह संदेश मिलता था तो उन्हें लगता कि ये संदेश वहां ब्रिटेन के राजस्व विभाग की ओर से भेजे गए हैं।

डरकर कई लोग इनके दिए नंबर पर फोन करते थे। इसके बाद यहां काल सेंटर में काम करने वाले कर्मी उन्हें झांसे में लेते थे। ये अपने शिकार को कर अदा करने के लिए राजी करते थे। लेनदेन के लिए ये लोग आनलाइन प्लेटफार्म का ही इस्तेमाल करते थे। जैसे ही इनके बताए खाते में पैसा आता तो ये लोग शिकार का मोबाइल नंबर ब्लाक कर देते थे। पुलिस को पता चला कि यहां ऐसे लोगों को ही नौकरी पर रखा जाता था जिनके बोलने का अंदाज ब्रिटिश अंग्रेजी बोली से मिलता हो, ताकि शक की गुंजाइश न हो।

बगैर कानून में बदलाव किए दिल्ली में नहीं लागू हो सकती है घर घर राशन स्कीम

नई दिल्ली । जिस घर घर राशन स्कीम (डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन) को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी है। इसे लेकर जनता में भी यह उत्सुकता हो रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। वास्तव में दोषी कौन है। क्या केवल इस मामलेू में राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं। इस बारे में खाद्य आपूर्ति से जुड़े कानून के जानकारों की मानें तो इस पर केवल राजनीति हो रही है। दिल्ली में घर घर राशन बांटने की स्कीम लागू ही नहीं हो सकती है। इसके लिए संसद में लाकर कानून में संशोधन करना पड़ेगा। दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में घर घर राशन बांटने का प्रावधान नहीं है।

खाद्य सुरक्षा मामलों में कानूनी मदद दे रहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार कहते हैं कि घर घर राशन स्कीम दिल्ली में लागू नहीं हो सकती है। उनके अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में राशन की होम डिलीवरी का प्रावधान नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद के माध्यम से कानून में बदलाव करना होगा। उसके बाद दिल्ली में यह स्कीम लागू हो सकती है। वह पिछले एक साल से यह बात कह रहे हैं। वह कहते हैं कि दिल्ली की राशन की दुकानों पर जनवरी से ई-पोस मशीन लगी हैं। मगर इन्हें चालू नहीं किया जा रहा है। वह इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। मगर यह बात समझ नहीं आ रही है कि इन मशीनों को शुरू नहीं किए जाने में किसका लाभ है। किसके दबाव में इन्हें शुरू नहीं किया जा रहा है। इन मशीनों को चालू होने के बाद केवल उन्हीं लोगों को राशन मिल पाएगा जिसके नाम से राशन कार्ड बने हैं। इससे भ्रष्टाचार दूर होगा।

दिल्ली में जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए शाही इमाम बुखारी ने पीएम मोदी से मांगी मदद

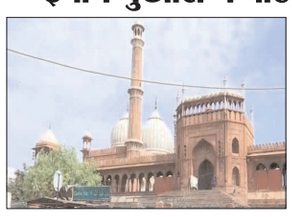

नई दिल्ली । जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता मांगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए निर्देशित करें। बता दें कि शुक्रवार की रात में आई तेज आंधी पानी से जामा मस्जिद की मीनार को नुकसान पहुंचा है। उसके एक मीनार में लगे कुछ पत्थर गिर गए हैं। ऐसे में जामा मस्जिद को मरम्मत की आवश्यकता है। वैसे लाकडाउन के पहले भी बुखारी की ओर से प्रधानमंत्री से मांगी गई सहायता पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जामा मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू किया था, लेकिन लाकडाउन के कारण काम रुक गया है। इस बीच मीनार की पत्थर गिरने की घटना हुई है।

दिल्ली में शख्स की शर्मसार करने वाली करतूत, पत्नी और बच्चों के साथ करता था कुकर्म

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली इलाके के मदनगीर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर ही अपने चार और पांच साल के बच्चों के साथ यौन अपराध करने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया कि पहले तो युवक केवल उसके साथ ही अप्राकृतिक दुराचार करता था, लेकिन कुछ दिन बाद पांच साल के बेटे के साथ भी यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया था। पीड़िता की शिकायत पर मालवीय नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2014 में मदनगीर की रहने वाली महिला की शादी सैनिक फार्म में रहने वाले युवक से हुई थी। दोनों के चार और पांच साल के दो लड़के हैं। युवक महिला के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने लगा और मना करने पर मारपीट करता रहता था। महिला मारपीट को बर्दाश्त करती रही, लेकिन युवक ने बच्चों के साथ भी वारदात करने की कोशिश की। इसके बाद महिला बच्चों को लेकर अपने पिता के घर आ गई।पीड़िता की शिकायत के अनुसार, दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम साल 2018 का है। महिला का आरोप है कि युवक उसे शिकायत करने पर धमकी देता था, इसलिए उसने अब तक शिकायत नहीं दी। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों पति पत्नी में पहले से विवाद चल रहा है। मामले में बच्चों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए गए हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि विवाद सभी एंगल से पूरे मामले की जांच की जाएगी। मामले बच्चे से जुड़ा है और बेहद ही संवेदनशील है। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह की मामले आ चुके हैं, जिनमें कई मामलों में कोर्ट द्वारा सजा भी सुनाई जा चुकी है।

दिल्ली अनलॉक 2.0 में बोले व्यापारी, ऑड-ईवन से बढ़ी परेशानी, फॉर्मूला से बढ़ रहा कन्फ्यूजन

नई दिल्ली । दिल्ली में आज सोमवार से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो गई है. इसके बाद दिल्ली की मार्केट्स आज से ऑड-ईवन फार्मूले के तहत खुल गई हैं. दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का ऑड-ईवन के तहत मार्केट में फॉलो भी किया जा रहा है. वहीं, कोरोनावायरस का भी पूरी तरीके से पालन करते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है. इसको लेकर पहले दिन खुले बाजारों की स्थिति क्या रही, इसको लेकर मार्केट एसोसिएशन और दुकानदारों से बातचीत की गई. आइए जानते हैं अनलॉक 2.0 के पहले दिन क्या कह रहे हैं दिल्ली के व्यापारी...

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मंडोली रोड मार्केट, राम नगर के कपड़ा व्यापारी पंकज शर्मा का कहना है कि मार्केट तो खुल गए हैं. लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है. कोरोना की वजह से लगे लॉक डाउन से लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई है. वहीं, व्यापारियों के लिए त्योहार का सीजन भी निकल चुका है. अब सिर्फ 29-30 जून का विवाह का एक मुहूर्त बचा है. मार्केट में ग्राहक नहीं है. अब अगला सीजन दीपावली के आसपास ही आएगा. पहले दिन बाजार बहुत ही हल्का रहा है. खारी बावली मार्केट के व्यापारी प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि मार्केट खुलने का पहला दिन सामान्य ही रहा है. व्यापारी के लिए ऑड-ईवन सिस्टम से दुकानों को खोलना संभव नहीं हो पा रहा है. लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है. और इसके लिए सभी सावधानियों का ध्यान भी रखा जा रहा है

दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के संयोजक और कपड़े के थोक व्यापारी राजेश मल्होत्रा का कहना है कि व्यापारियों का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है. दिल्ली सरकार की ओर से अनलॉक 2.0 की शुरुआत आज से की गई है. व्यापारी अपनी दुकानों को ऑड-ईवन सिस्टम को लागू करके खोल रहे हैं. वहीं, कोविड-19 का पालन भी करा रहे हैं. आज कुछ दुकानें ऐसी भी खोली गई हैं जो कि लंबे समय से बंद पड़ी थी लेकिन उनका आज खुलने का नंबर नहीं था. यह सिर्फ लंबे समय से जमी धूल और साफ-सफाई के लिए ही खोली गईं. दुकानों पर एक और दो नंबर अंकित किए गए हैं.

ऑटो पार्ट्स मार्केट एसोसिएशन, कश्मीरी? गेट के प्रधान और व्यापारी विनय नारंग बताते हैं कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन फार्मूला दुकानों के खोलने के लिए पूरी तरीके से गलत है. व्यापारी के लिए इस सिस्टम के तहत अपने कारोबार को चलाना संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर कोई दुकानदार या व्यापारी नट लेने के लिए हरियाणा से आता है तो उसको आज बोल्ट की दुकान खुली मिलेगी. लेकिन नट लेने के लिए उसे कल आना पड़ेगा. इससे उसका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होंगे. इसलिए ऑड- इवन फार्मूला बेहद गलत है. जहां तक कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन कराने की बात है तो दुकानदारों ने बगैर मास्क लगाए आने वाले लोगों को सामान देने से मना करने वाले बोर्ड लगाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि पूरी मार्केट को सुबह 5 बजे ही सैनिटाइज करा दिया गया.

चांदनी चौक के कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए प्रदीप तिवारी बताते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से खाली है. आज पहला दिन है. अभी लोगों की आवाजाही होने में वक्त लगेगा. अगले दो-चार दिन में मार्केट में लोगों का आना जाना शुरू हो सकेगा. लेकिन यह भी बात है कि अभी ऑड-ईवन के तहत खुली दुकानों को लेकर लोगों को कुछ समझ नहीं आ पा रहा है.

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा का कहना है कि मार्केट ऑड-ईवन के तहत खोली गई है. इसके लिए छोटी गलियों की दुकानों के लिए कलर कोडिंग की गई है. एक साइड रेड और दूसरी तरफ ग्रीन कलर किया गया है जिससे कि ऑड-ईवन सिस्टम को लागू किया जा सके. वहीं, चौड़ी गलियों में दुकानों पर नंबरिंग की गई है. नंबर के हिसाब से ही यह दुकानें ऑड-ईवन दिन में खुलेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराने का भी काम किया जा रहा है. उन व्यापारियों को ज्यादा परेशानी हो रही है जो कि आसपास के राज्यों से माल लेने के लिए आ रहे हैं और आज उनकी माल लेने की दुकानें नहीं खुली हुई है उनको वापस जाना पड़ रहा है. बाबरपुर 100 फुटा रोड पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले दुकानदार आशुतोष वशिष्ठ का कहना है कि ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानों को आज से खोला गया है. लेकिन यह फार्मूला सही नहीं है. व्यापारी पहले ही लॉक डाउन की वजह से और पिछले 1 साल से कोरोना काल में पूरी तरीके से मर चुका है.

संपादकीय

मांग बढ़ेगी, तभी बेरोजगारी कम होगी

करीब 50 हफ्तों के बाद 16 मई को खत्म हुए सप्ताह में ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़कर 14.34 फीसदी हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी दर में इसी तरह से इजाफा हुआ है और शहरों में वह बढ़कर 14.71 प्रतिशत हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन को बताया जा रहा है, जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद देशव्यापी तो नहीं, लेकिन लगभग 90 फीसदी हिस्से पर किसी न किसी रूप में लागू है। लॉकडाउन में रोजगार का खत्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे में हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देते हैं। हालांकि, इस साल रोजगार पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, जितना पिछले साल पड़ा था। बीते साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी खत्म हुई थी, जबकि करीब 20 करोड़ लोगों के काम प्रभावित हुए थे। यह समझना चाहिए कि रोजगार की तुलना में काम अधिक प्रभावित होता है। जैसे, लॉकडाउन में दफ्तरों और स्कूल-कॉलेजों के बंद होने से सरकारी कर्मियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों आदि के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन काम के बंद होने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि इससे उत्पादन बंद हो जाता है। जाहिर है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। इस साल आंशिक लॉकडाउन लगा है, लेकिन फिर भी आपूर्ति श्रृंखला तो प्रभावित हुई ही है। जगह-जगह कारखाने बंद हुए हैं और कुटीर उद्योगों पर इसका खासा असर पड़ा है। संगठित क्षेत्र को भी लॉकडाउन ने प्रभावित किया है। चूंकि इसमें अब बड़े पैमाने पर निविदा पर रोजगार दिए जाते हैं, इसलिए यहां कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाना आसान है।

लोगों में फैलते भय ने भी रोजगार क्षेत्र को प्रभावित किया है। दूसरी लहर को देखते हुए शहरों से फिर मजदूरों का पलायन हुआ। चूंकि बिना जांच के वे गांवों की तरफ रवाना हुए, इसलिए वायरस का प्रसार गांव-गांव में हो गया है। चिकित्सा जगत का एक मॉडल कह रहा है कि संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनसे करीब 10 गुना अधिक संक्रमण हुआ है, और मौतें भी तीन से आठ गुना ज्यादा हुई हैं। यह दहशत तब और बढ़ गई, जब मध्य वर्ग और ऊंचे तबके में भी महामारी का प्रसार बढ़ा। भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले अखबारों में आधे पन्ने पर शोक-संदेश छपा करते थे, लेकिन अब यह बढ़कर चार-चार पन्ने तक हो गए हैं। चूंकि यही वर्ग ज्यादा खपत करता है, इसलिए बीमारी के आने के बाद इसने अपनी खपत कम कर दी। फिर, इन वर्गों का स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ गया है। गरीब तबका तो कर्ज लेकर जैसे-तैसे अपना इलाज करा रहा है, लेकिन मध्य व उच्च वर्ग अपनी बचत खर्च कर रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका ने भी उन्हें बहुत सोच-समझकर खर्च करने के लिए प्रेरित किया है। संभवतः इसी वजह से रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोग अब नकदी ज्यादा जमा करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि कोई परेशानी हुई, तो नकद राशि ही मददगार साबित होगी। इन सबसे हमारी खपत बुरी तरह गिर गई है, और खपत के गिरने का असर उत्पादन पर पड़ा है। उत्पादन कम होने का अर्थ है, नए निवेश का कम होना, जिससे स्वाभाविक तौर पर रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ा है। सवाल है, अब आगे क्या किया जाए? टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को शायद ही त्वरित फायदा हो सकेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अपने यहां टीकेकरण को लेकर स्पष्ट नीतियों का अभाव है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने समय रहते टीके के ऑर्डर दे दिए थे, इसीलिए उन्होंने तेजी से टीकाकरण किया है। नतीजतन, वहां की 50 फीसदी आबादी को टीका लग चुका है, जिसका फायदा उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। अपने यहां अव्वल तो ऑर्डर देने में देरी हुई, और फिर जैसे-तैसे टीकाकरण शुरू कर दिया गया। कहा गया कि पहले डेढ़ महीने में एक करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जबकि सवा अरब की आबादी के लिहाज से हमें 10 करोड़ से शुरुआत करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि 'हर्ड इम्यूनिटी' के लिए 60 फीसदी आबादी का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है। यानी, 10 महीने में 84 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराकें लग जानी चाहिए। इसका मतलब है, हमें टीके की लगभग 170 करोड़ खुराक की जरूरत है। इसे अगर 10 महीने में बांटें, तो हर महीने हमें 17 करोड़ खुराक चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो सका। इससे न सिर्फ वायरस के नए-नए इलाकों में फैलने का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि उसके म्यूटेट होने की आशंका भी है। अगर वायरस म्यूटेट हो गया, तो यह उन इलाकों में फिर से फैल सकता है, जहां एक बार यह तबाही मचा चुका है। ऐसे में, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। जब तक लहर बनी रहती है, हमें लॉकडाउन के भरोसे ही इसके प्रसार को थामना होगा।

दूसरा काम स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने का है। 'टेस्टिंग' और 'ट्रेसिंग' के साथ-साथ 'जीनोम टेस्टिंग' पर हमें जोर देना चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि वायरस हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अभी वायरस को लेकर कई सूचनाएं ब्रिटिश व अमेरिकी प्रयोगशालाएं से आ रही हैं। हमें खुद यह प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए, मगर विडंबना यह है कि विश्वविद्यालयों के बंद रहने से ऐसे शोध कम हो रहे हैं। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। एक बड़ी जरूरत गरीब तबके को मदद देने की है। उन्हें अगर नकदी सहायता मिलेगी, तो खपत बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ सकती है। ऐसी ही सहायता मध्यवर्ग को भी चाहिए। इस साल बजट में मनरेगा का आवंटन 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 70 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह कटौती नहीं होनी चाहिए। चूंकि ग्रामीण इलाकों में भी वायरस का प्रसार हो गया है, इसलिए वहां भी उत्पादकता अब प्रभावित होगी। इसे ध्यान में रखकर हमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को पर्याप्त समर्थन देना होगा। जाहिर है, बजट की समीक्षा करते हुए उसे दुरुस्त करना होगा, और जरूरी मदों में खर्च बढ़ाते हुए उन-उन जगहों पर कटौती करनी होगी, जहां ऐसा करना संभव है। इससे राजकोषीय घाटा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और नई लहर से निपटने के लिए भी हम तैयार रह

प्रवीण कुमार सिंह

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन का समय

भविष्य में यही चिकित्सा पदाधिकारी जिला स्तर पर कुछ साल का अनुभव अर्जित करने के बाद विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के परियोजना अधिकारी और केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय सचिवों के विभिन्न रैंकों और अन्य संबंधित पदों तक की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। इंडियन मेडिकल सिर्वस चिकित्सा पेशेवरों को नीति बनाने का एक हिस्सा बनने और प्रशासन में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली स्थिर हो सकेगी।

कोरोना महामारी ने बीते करीब डेढ़ साल में बहुत कुछ सिखाया है। इस महामारी ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में नीतिगत रूप से भी आमूलचूल बदलाव करने का संकेत दिया है। हमें सिखाया है कि देश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। इस दौरान स्वास्थ्य प्रशासकों तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण जिला स्तर पर कोविड का प्रबंधन करने में भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के गठन का प्रस्ताव पिछले करीब पांच दशकों से लटका हुआ है। कई समितियों ने समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा के गठन की सिफारिश की। आजादी के बाद सर्वप्रथम देश में एक अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर गठित का सुझाव मुदलियार समिति द्वारा दिया गया। समिति ने अपने सुझाव में कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण की समस्याओं से संबंधित कर्मियों के पास एक समग्रतापूर्ण और विस्तृत दृष्टिकोण तथा राज्य स्तर पर प्रशासन का समृद्ध अनुभव होना चाहिए। इसके बाद साल 1973 में करतार सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि संक्रामक रोग नियंत्रण, निगरानी प्रणाली, डाटा प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के संबंध में चिकित्सकों को कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है और न ही उन्हें ग्रामीण परिवेश तथा विभिन्न सामाजिक आयामों की समझ है, ऐसे में ये चिकित्सक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अनुपयुक्त हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कैडर के लिए 1997 में पांचवें वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी। वर्ष 2017 में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इस बात की वकालत की गई है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर की शुरुआत की जानी चाहिए। इसके माध्यम से कुछ विशिष्ट, सर्मिपत एवं प्रशिक्षित लोगों

को चुना जा सकेगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकेंगे।

इसी साल मार्च में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संसदीय समिति ने अपनी अनुदान संबंधी मांगों पर अपनी 126वीं रिपोर्ट में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस की तरह ही अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के रूप में एक अलग कैडर गठित करने का सुझाव दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी का मुकाबला करने के दौरान कोरोना योद्धाओं की अविश्वसनीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा भविष्य में संभावित महामारी से निपटने के लिए देश में एक अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा मददगार साबित हो सकती है। समिति का मानना है कि स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं की सफलता दर को बढ़ाने और घातक बीमारियों से लड़ने के लिए नीतिगत कार्यक्रम तथा कार्रवाई का विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य सेवा कुशल स्वास्थ्य प्रबंधक प्रदान करेगी।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भारतीय चिकित्सा सेवा अस्तित्व में थी। वर्ष 1763-64 में चिकित्सा सेवाएं सबसे पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई। ये सेवाएं सेना के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए चिकित्सकों और सहायकों की भर्ती और तैनाती जैसे कार्यों को अंजाम देती थीं। वर्ष 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों सेवाओं पर सीधा नियंत्रण कर लिया। इन्हें एकल भारतीय चिकित्सा सेवा में रखा। अगस्त 1947 में इसे समाप्त कर दिया गया था। जीवविज्ञानियों का मानना है कि कोरोना न तो पहली महामारी है और न ही यह अंतिम महामारी होगी। दरअसल, तेजी से वैश्वीकृत होने के साथ-साथ त्वरित शहरीकरण के मार्ग पर अग्रसर होती दुनिया में इस तरह की महामारी के पूरे विश्व में तेजी से फैलने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करना समय की मांग है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर बनाना भी आवश्यक हो गया है, जिसमें विभिन्न विषयों जैसे कि महामारी विज्ञान, जैव सांख्यिकी, जन सांख्यिकी और सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान में प्रशिक्षित पदाधिकारियों को रखा जाना चाहिए। अच्छी बात है कि नीति आयोग ने एक आदर्श सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न हितधारकों से परामर्श भी किया है, जो सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों को अपनाते रहे हैं।

पिछले कई दशकों का अनुभव बताता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की केंद्र पोषित और सहायतित योजनाओं के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम भारत में सामने नहीं आ सके हैं। आज अरबों रुपये का बजट राज्यों को जारी किया जाता है, मगर चिकित्सा और स्वास्थ्य की दिशा में नतीजे उत्साहवर्धक नहीं हैं। चिकित्सा समुदाय भी कई कारणों से भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन के पक्ष में है। पहला कारण तो यह है कि अगर चिकित्सा सेवाओं के अधिकारियों को आइएएस की तरह सुविधाएं और वेतन मिलने लगें, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकारी बनने के लिए प्रतिभावान युवा आर्किषत होंगे। इससे डॉक्टरों का पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी और पब्लिक हेल्थकेयर में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी। दूसरी बात, वर्तमान में संयुक्त मेडिकल परीक्षा के जरिये जिन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उन्हें चिकित्सा का तो ज्ञान होता है, लेकिन उनमें प्रशासनिक क्षमता की कमी होती है। व्यापक अनुभव रखने वाले चिकित्सक भी भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ हैं, जिससे हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऐसे में अलग कैडर गठित करके अगर चिकित्सा अधिकारियों को भी आइएएस तथा आइपीएस की तर्ज पर ही नियुक्ति के बाद उन्हें दो वर्ष के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, तत्पश्चात उन्हें सेवा देने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे उनके भीतर संबंधित प्रशासनिक गुणों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। इसका एक फायदा यह भी है कि अलग कैडर गठित करने से आइएएस अधिकारियों के हाथों में अत्यधिक और मनमानी शक्तियों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। भविष्य में यही चिकित्सा पदाधिकारी जिला स्तर पर कुछ साल का अनुभव अर्जित करने के बाद विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के परियोजना अधिकारी और केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय सचिवों के विभिन्न रैंकों और अन्य संबंधित पदों तक की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। इंडियन मेडिकल सिर्वस चिकित्सा पेशेवरों को नीति बनाने का एक हिस्सा बनने और प्रशासन में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली स्थिर हो सकेगी। ऐसा संभव होता है तो गुणवत्ता से परिपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल कार्यान्वयन से गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। उनका स्वास्थ्य खर्च कम होने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही स्वास्थ्य कैडर के निर्माण से उन नौकरशाहों को मुक्त किया जा सकेगा, जिनका महत्व अन्य विभागों में अधिक है।

देश में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया को बनाया जाए सरल

पिछले एक साल से अधिक समय से दुनिया भर के कोरोना विशेषज्ञ भारत के नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य तंत्र को निरंतर यह चेतावनी दे रहे हैं कि देश को कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बहुत जल्द धरातल पर ठोस कदम उठाते हुए तैयार करना होगा। लेकिन धरातल पर किस तरह की व्यवस्था की गई थी, संक्रमण की दूसरी लहर ने इसकी पोल खोल दी है। अब तीसरी लहर की आशंका और उसके घातक असर से बचाव के लिए देश में जल्द से जल्द कोरोना रोधी टीके की किल्लत को दूर करते हुए उसे लगवाने की प्रक्रिया को सरल बनाना बेहद जरूरी है।

सरकार को देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को बेहद तेज व सरल करने के लिए जल्द से जल्द युद्धस्तर पर कारगर रणनीति बनानी होगी। वर्तमान में टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल है। टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफार्म के मोबाइल पर एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आसानी से शहरी क्षेत्रों में ही ओटीपी नहीं आ पाता है, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के समय अगर आपका ओटीपी आ भी जाए और आसानी से नाम भी जुड़ भी जाए, तो टीका लगवाने के लिए अपना समय बुक करवाने में लोगों के छक्के छूट जाते हैं। लगातार प्रयास से समय भी मिल जाए तो धरातल पर टीकाकरण केंद्र को ढूंढना बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वेबसाइट पर अधिकांश टीकाकरण केंद्रों का पूरा पता नहीं दिया गया है।

सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो तब शुरू होती है जब कई बार टीकाकरण केंद्र पर भी पहुंचने पर पता चलता है कि यह टीकाकरण केंद्र तो पिछले कई दिनों से खुला ही नहीं है या केंद्र पर टीका उपलब्ध ही नहीं है। सरकार को इस तरह की सभी गंभीर समस्या की तरफ तत्काल ध्यान देना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण ईमानदारी से घर में रहकर पालन कर रहा था, वो सिस्टम की इस लापरवाही भरी प्रक्रिया में कोरोना वायरस की चपेट में आकर संक्रमित हो सकता है। वैसे अगर सरकार वास्तव में देश को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त करना चाहती है, तो उसको पोलियो बीमारी के टीके की तरह कोरोना के टीकाकरण के कार्यक्रम को सरल व तेज बनाना होगा। हालांकि इसके लिए टीके को सुरक्षित रखने के लिए जरूरत के मुताबिक तापमान व भंडारण की व्यवस्था करना सरकार व निर्माता कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।

देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए विश्व में जितने भी पूर्ण रूप से सुरक्षित कोरोना के टीके बन रहे हैं, भारत सरकार को उनको जल्द से जल्द सरकारी स्तर पर प्रयास करके देश में लाना चाहिए, उनको कम से कम खुले बाजार में तो जनता के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे जो लोग पैसा देकर कोरोना का कोई भी टीका बाजार से खरीद कर लगवाना चाहते हैं वो निजी अस्पतालों के माध्यम से जल्द टीका लगवा सकें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सरकारी तंत्र पर से टीका खरीदने का भार काफी कम हो जाएगा और देश में बहुत सारे लोगों का समय से टीकाकरण भी हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में आजकल राज्य स्तर पर कोरोना के टीके खरीदने के लिए विश्वस्तर पर टेंडर निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार को राज्यों से सामंजस्य करके इस स्थिति पर लगातार नजर रखनी होगी कि कोरोना का टीका बनाने वाली कोई भी कंपनी राज्यों से अधिक दाम नहीं वसूल सके।

तीन बच्चों की इजाजत

चीन सरकार ने अपनी बहुचर्चित बर्थ कंट्रोल पॉलिसी में अहम बदलाव लाते हुए घोषणा की है कि अब वहां हर विवाहित जोड़े को तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत होगी। चीन में 1980 से सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पूरी सख्ती से लागू थी। 2016 में अचानक इस नीति में संशोधन करते हुए कहा गया कि सभी मैरिड कपल दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पांच साल बाद अब इस सीमा को बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति में इस तरह का बार-बार बदलाव बताता है कि इस नीति में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। जब चीन ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू करना शुरू किया, तब भी यह कहा गया था कि सभ्य समाज में ऐसी जबर्दस्ती अच्छी चीज नहीं है और यह भी कि आगे चलकर इस नीति के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इन बातों से बेपरवाह चीन ने यह नीति जारी रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर काफी हद तक काबू पा लिया और तेज आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया। लेकिन इसके साथ ही वहां की आबादी का स्वरूप भी बदलता गया। समाज में वृद्धों-बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई और श्रमशील आबादी का प्रतिशत कम होता गया। नतीजा यह कि जहां आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं आबादी के घटने का खतरा भी उपस्थित हो गया है।

आंकड़े बताते हैं कि चीन में जन्म दर पिछले चार सालों में लगातार गिरी है। पिछले साल वहां कुल 1.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 2019 में 1.46 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। एक साल में यह 18 फीसदी की गिरावट थी। वहां फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला द्वारा पूरे जीवन काल में जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या 1.3 है, जबकि आबादी का समान स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या 2.1 मानी जाती है। जाहिर है, 2016 में बच्चों की संख्या में छूट देने का कोई लाभ नहीं हुआ और विशेषज्ञों के मुताबिक इसे बढ़ाकर तीन करने का भी शायद ही कोई फायदा हो। वजह यह है कि लोग इस छूट का इस्तेमाल करने की मनर्स्थिति में ही नहीं हैं। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के दौर में पैदा हुए और पले-बढ़े लोग यह महसूस नहीं कर पा रहे कि बच्चे को भाई-बहनों की भी जरूरत होती है, उनके व्यक्तित्व के विकास में इससे मदद मिलती है। बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा-दीक्षा का खर्च बढ़ गया है। बच्चे के साथ-साथ परिवार के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी संभालने में पस्त लोगों के लिए बच्चों की संख्या बढ़ाने की सोचना मुश्किल है। यही नहीं, देर तक काम करने का कल्चर भी इसमें बाधा बन रहा है। कुल मिलाकर देखें तो सरकार की सख्ती ने चीनी समाज को एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया है, जहां से निकलने की कोई सीधी सरल राह नहीं दिख रही।

नेपाल में लंबे समय से जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच संविधान की जीत

उल्लेखनीय है कि ओली ने 15 फरवरी 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पूर्व ओली और प्रचंड ने सरकार गठन करने के लिए अपने-अपने दलों का विलय कर दिया था, लेकिन दोनों नेता और दल कभी भी एकदूसरे को फूटी आंख नहीं भाए। प्रचंड हमेशा यह कहते रहे कि एक व्यक्ति-एक पद की सहमति बनी थी, लेकिन ओली प्रधानमंत्री के साथ-साथ संगठन पर भी काबिज हैं। दूसरी ओर ओली प्रचंड पर सरकार विरोधी रुख और सरकार नहीं चलाने के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं।

लंबे समय से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नेपाल फिर मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर आ गया है। नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने सभी दलों को सरकार बनाने का मौका दिया, ताकि मध्यावधि चुनाव को टाला जा सके, लेकिन सत्ताधारी दल समेत सभी दल सरकार के गठन में नाकाम रहे तो उन्होंने संसद भंग करते हुए नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। हालांकि इससे पूर्व एक बार फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी दलों ने सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा किया था। चूंकि कुछ सांसदों के नाम इन दोनों पत्रों पर कॉमन थे, इसीलिए राष्ट्रपति भंडारी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रतिनिधि सभा संसद को भंग कर दिया। नेपाल में अब नवंबर में चुनाव होंगे। सच मानिए, नेपाल में पेंडुलम की मानिंद सियासत को अब कड़ा इम्तिहान देना होगा, क्योंकि संविधान बनने के बाद नेपाल में गठबंधन की सियासत फेल हो गई है।

नेपाली प्रधानमंत्री ओली और चार बार वहां के पूर्व पीएम रहे शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने ही राष्ट्रपति भंडारी को अपने-अपने हक में समर्थक सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद गेंद राष्ट्रपति के पाले में आ गई थी। मगर राष्ट्रपति ने दोनों के दावों को संवैधानिक तराजू पर तौलने के बाद इन्हें खारिज कर दिया। नेपाल का राजनीतिक संकट 21 मई को उस वक्त और गहरा गया थी, जब प्रधानमंत्री ओली और विपक्षी दलों दोनों ने ही

राष्ट्रपति को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र देकर अपनी-अपनी सरकार गठन का दावा ठोका था। प्रधानमंत्री ओली विपक्षी दलों के नेताओं से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के अनुसार पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी सीपीएन-यूएमएल के 121 सदस्यों और जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल (जेएसपी-एन) के 32 सांसदों के समर्थन के दावे वाला पत्र सौंपा। इससे पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 149 सांसदों का समर्थन होने का दावा किया था। देउबा प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे।

प्रधानमंत्री ओली ने संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने में 20 मई को अनिच्छा जता दी थी। नेपाली कांग्रेस (एनसी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर), जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के उपेंद्र यादव नीत खेमे और सत्तारूढ़ सीपीएन-यूएमएल के माधव नेपाल नीत ग्रुप समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने प्रतिनिधि सभा में 149 सदस्यों का समर्थन होने का दावा किया था, जबकि पीएम ओली की माई रिपब्लिका वेबसाइट के अनुसार इन सदस्यों में नेपाली कांग्रेस के 61, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) के 48, जेएसपी के 13 और यूएमएल के 27 सदस्यों के शामिल होने का दावा किया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी गठबंधन के नेता 149 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाला पत्र राष्ट्रपति को सौंपने के लिए उनके सरकारी आवास गए। इस पत्र में शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की गई थी। देउबा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वर्ष 2017 में आम चुनावों के बाद से विपक्ष के नेता हैं। गेंद अब राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पाले में थी, इसीलिए उन्होंने मध्यावधि चुनाव कराने का बड़ा फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 121 सीटों के साथ सीपीएन-यूएमएल सबसे बड़ा दल है। इस समय बहुमत सरकार बनाने के लिए 136 सीटों की दरकार है।

इससे पहले भी नेपाल में वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर पिछले वर्ष 20 दिसंबर को राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद से नेपाल की सियासत में खलबली मच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग किए जाने के फैसले को पलट दिया था। नेपाल की शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र समशेर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए संसद को बहाल कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने 13 दिनों के भीतर संसद का सत्र आहूत करने का आदेश दिया। दरअसल अचानक संसद भंग करने के ओली सरकार के फैसले का उन्हीं की पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पुष्प कमल दहल प्रचंड और देश की जनता ने भारी विरोध किया था। इसके बाद संसद भंग किए जाने को लेकर अलग-अलग 13 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं, जिन पर 20 फरवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था।

उल्लेखनीय है कि ओली ने 15 फरवरी 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पूर्व ओली और प्रचंड ने सरकार गठन करने के लिए अपने-अपने दलों का विलय कर दिया था, लेकिन दोनों नेता और दल कभी भी एकदूसरे को फूटी आंख नहीं भाए। प्रचंड हमेशा यह कहते रहे कि एक व्यक्ति-एक पद की सहमति बनी थी, लेकिन ओली प्रधानमंत्री के साथ-साथ संगठन पर भी काबिज हैं। दूसरी ओर ओली प्रचंड पर सरकार विरोधी रुख और सरकार नहीं चलाने के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

पंजाब में आप का हाल- एक कदम आगे और दो कदम पीछे, पूरे राज्य में आधार बनाना चुनौती

चंडीगढ़ । राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर आम आदमी पार्टी का आधार बनाने वाले पंजाब में पार्टी हमेशा ही एक कदम आगे और दो कदम पीछे चलती रही है। यह क्रम 2015 से शुरू हुआ और 2021 तक बदस्तूर जारी है। आप 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही एक बार फिर दावेदारी ठोक रही है लेकिन पार्टी का पूरे पंजाब में कभी भी कोई मजबूत आधार नहीं रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य में सत्ता हासिल करने के दावे कर रही थी, लेकिन 20 सीटों पर ही सिमट गई। इस बार पार्टी को मजबूत आधार देने वाले कई नेता उसका साथ छोड़ चुके हैं। राज्य के दो हिस्सों माझा और दोआबा की 48 सीटों में से 2017 में केवल तीन विधानसभा सीटों पर ही आप को सफलता मिली थी। मालवा में 69 में से 17 सीटों मिल गई थीं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में 24.40 फीसद वोट शेयर लेने वाली आप 2019 में केवल 7.37 फीसद वोट तक ही सिमट गई। आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायकों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद आप एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब आप पूरे देश में विफल हुई थी तो पंजाब में चार सीटों पर उसे विजय मिली थी। यह चारों लोकसभा सीटें मालवा क्षेत्र से थीं। लेकिन उसके बाद जल्द ही पार्टी में विघटन की चिंगारी सुलगने लग गई थी। दो सांसदों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आप ने 2015 में अपने दो सांसदों, पटियाला से धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब से हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी ने दोबारा इन दोनों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश नहीं की। धर्मवीर गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में आप का विश्वास बढ़ा हुआ था और आप नेता 117 में से 108 सीटें जीतने तक का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणामों ने उनको निराश ही किया। आप के केवल 20 प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाए। अहम पहलू यह रहा कि इसमें से सुखपाल खैहरा को छोड़कर बाकी के सारे 19 विधायक पहली बार चुनाव लड़े और जीते थे। दोआबा में भुलत्थ से सुखपाल खैहरा, रूपनगर से अमरजीत सिंह संदोआ और गढ़शंकर से जय किशन ही जीत हासिल कर पाए। माझा में एक भी सीट नहीं मिली। इस तरह दोआबा और माझा की 48 में से 45 सीटों पर आप कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब फिर पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तलाशने में जुट गई है लेकिन जिस तरह से उसकी लोकप्रियता लगातार कम होती गई है, उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।

लुधियाना के बीसीएम स्कूल में समर बोनांजा में विद्यार्थी निखार रहे प्रतिभा

लुधियाना । बीसीएम स्कूल चंडीगढ़ रोड ने 15 दिवसीय वर्चुअल समर बोनांजा वर्चुअल कैंप की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में छात्रों के गुप्त कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए असंख्य गतिविधियां आयोजित की जा रही है। छात्रों ने खेल और योग से लेकर कला और शिल्प तक, ओलंपियाड से लेकर बुनियादी टेबल मैनर्स और कुकिंग फायर, संगीत और नृत्य से लेकर युवा वक्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक और कई अन्य गतिविधियों में खुद को नामांकित किया है। स्कूल के कक्षा तीसरी से नौवी तक के लगभग तीन हजार छात्रों ने उत्साहपूर्वक कायाकल्प, मनोरंजन और सुदृढीकरण के केंद्र का हिस्सा बनने के लिए नामांकन किया है। स्कूल छात्रों की एकाग्रता बढ़ाने, सीखने, कल्पना में सुधार करने और सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए गतिविधियों से जोड़ रहा है। वहीं शिविर का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने का अवसर प्रदान करना और उन्हें अपनी पसंद की विभिन्न गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। प्रिंसिपल डीपी गुलेरिया ने छात्रों को समर बोनांजा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हम सभी को अपने कौशल और प्रतिभा को विकसित करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियां दो उद्देश्यों की पूर्ति पहली छात्रों को क्रिएटिव बनाने और दूसरी उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अवसर देती हैं। कोरोना महामारी के चलते अधिकतर समारोह आनलाइन ही आयोजित किए जा रहे हैं।

फ्रांस में चंडीगढ़ हेरिटेज आइटम्स नीलाम, 21 लाख में बीका सोफा

चंडीगढ़ । चंडीगढ़ की हेरिटेज आइटम्स पर अभी भी गौरों की नजर वैसे ही है जैसे आजादी से पहले होती थी। वह हेरिटेज फर्नीचर और दूसरी आइटम के लिए क्रेजी हैं। यही वजह है कि लगातार कुछ दिनों के अंतराल बाद ही चंडीगढ़ की हेरिटेज आइटम्स कि विदेश में ऑक्शन हो रही हैं। विदेशी नीलाम घर ग्लोबली यह ऑक्शन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह ही फ्रांस के पेरिस में चंडीगढ़ के क्रिएटर पियरे जेनरे के कजिन पियरे जेनरे का डिजाइन फर्नीचर नीलाम हुआ था। अब दोबार से एक और ऑक्शन हो गई है। यह ऑक्शन फ्रांस के चैंटली शहर में हुई है। नौ आइटम 93 लाख रुपये में बेची गई हैं। चंडीगढ़ हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल के मेंबर एडवोकेट अजय जग्गा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। फ्रांस में भारत के अंबेसेडर जावेद अशरफ, इंडियन एंबेसी पेरिस में फर्स्ट सेक्रेटरी विनाश कुमार सिंह को भी शिकायत भेजी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी प्रति भेजी गई है।

टीक सोफा सवा 21 लाख में हुआ नीलाम- ईजी आर्मचेयर का जोड़ा साढ़े चार लाख रुपये में बेचा गया है। फाइल रैक 10.63 लाख रुपये में नीलाम किया गया। ऑफिस केन चेयर 4.43 लाख में बेची गई। टीक टेबल 10.19 लाख रुपये में नीलाम की गई। छह डाइनिंग चेयर्स का सेट 15.3 लाख रुपये में नीलाम किया गया। एडवोकेट चेयर 19.45 लाख रुपये में नीलाम हुई। टीक सोफा बैक रेस्ट के साथ 21.22 लाख रुपये में बेचा गया।

साल 2011 से रोक, फिर भी विदेश पहुंच रही हेरिटेज आइटम्स- गृह मंत्रालय ने इस फर्नीचर को देश की सरहद से बाहर भेजने पर रोक लगा रखी है। उसके बाद भी इसकी तस्करी रुक नहीं रही है। यह लगातार विदेशी नीलाम घरों तक पहुंच रहा है। तस्कर गिरोह इसमें सक्रिय है। वह महिलाओं को इसके लिए निशाना बना रहा है। महिलाओं से यह काम कराते हैं। कई बार चोरी करते महिलाओं को पकड़ा भी गया। लेकिन जांच एजेंसी कभी भी मुंबई बेस्ड मुख्य सरगना तक नहीं पहुंच पाई।

झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, जानें विस्तार से

रांची । ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का बकाया भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करेगी। इसके तहत बिजली बिल की बकाया राशि के समायोजन के लिए करार होगा। बकाए बिल की राशि का भुगतान उपभोक्ता बगैर डीले पेमेंट सरचार्ज के कर पाएंगे। शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद में झारखंड बिजली वितरण निगम के इस प्रस्ताव की मंजूरी से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कई विधायकों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के उपभोक्ता बकाए बिल के ज्यादा राशि को लेकर परेशान हैं। इसका निदान इस निर्णय से होगा। इसमें स्थानीय स्तर पर बिजली वितरण निगम के पदाधिकारी उपभोक्ताओं की मदद कर चार समान किश्त में राशि लेने की पहल करेंगे। उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा कि बकाए बिल पर उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा वे कानूनी प्रक्रिया के दायरे में भी नहीं आएंगे। इस योजना के लिए 31 मई 2021 तक के बकायेदारों को लाभ देने पर विचार होगा। एक किश्त करीब 25 प्रतिशत राशि की होगी। शेष बकाया पर कोई अधिभार योजना के अंतर्गत नहीं देय होगा। हालांकि बिजली बकाए बिल के कारण थाने में जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने निर्णय किया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा सके। बिजली से जुड़े एक अन्य फैसले में रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अब उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में ही कोरोना कर्फ्यू, 24 घंटों में मिले 727 नए संक्रमित

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण लगता दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जबसे खुद ग्राउंड जीरो पर उतारकर कोरोना मैनेजमेंट की निगरानी कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार संक्रमण की दर में गिरवाट देखने को मिल रही है। सीएम योगी के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फार्मूले का ही असर है कि अब प्रदेश में संक्रमण दर शून्य के आसपास पहुंच चुकी है।

बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 727 नए मामले प्रदेश भर में मिले। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू से अब लगभग पूरा प्रदेश राहत पा चुका है। 600 से कम सक्रिय मामले होते ही सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करते हुए सहारनपुर को भी छूट देने का निर्देश दिया। अब सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में ही 600 से अधिक सक्रिय केस होने की वजह से वहां प्रतिबंध लागू है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इसमें बताया कि सहारनपुर में भी कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। लिहाजा इन्हें कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई। यहां भी अन्य 72 जिलों की तरह शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी पांच दिनों में सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार खुल सकेंगे। वहीं, लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी 600 से अधिक हैं। इनके संबंध में मंगलवार को विचार किया जाएगा।

समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि अन्य राज्य कोरोना नियंत्रण में उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे हैं। उत्तर प्रदेश पांच करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट करने वाला अकेला राज्य है। प्रदेश के किसी जिले में 100 से अधिक कोरोना केस नहीं आए हैं, जबकि यूपी से आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में कल 13,000 केस और अभी तक एक लाख से ज्यादा मौते हो चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश में चौबीस घंटों के दौरान तीन लाख दस हजार कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें संक्रमण के 727 नए मामले आए हैं। इस दौरान 2,860 लोगों ठीक होने के बाद जिस्चार्ज कर दिया गया है। अब राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.2 फीसद पहुंच चुकी है। राज्य में अब कुल एक्टिव केस 15,600 है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ दो लाख 54 हजार वैक्सीन डोज लोगों को दी जा चुकी है। अब सिर्फ मेरठ लखनऊ और गोरखपुर में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। अन्य सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं।

लालू की एक और बेटी कूदी ट्विटर वार में, आते ही सुशील मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा

पटना । बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जानेवाले लालू यादव जेल से जमानत पर छूटते ही सीएम नीतीश कुमार सहित विपक्ष पर हमला तेज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा के घर पर स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ ही बिहार की राजनीति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वे ट्विटर के माध्यम से बिहार की पॉलिटिक्स में लगातार सक्रिय हैं और सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। उनके अलावा उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ज्यादातर ट्विटर पर ही राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के निशाने पर ज्यादातर बिहार सरकार, नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं। उनके अलावा सिंगापुर में रहनेवाली लालू-राबड़ी की दूसरी पुत्री रोहिणी आचार्या भाईयों की राजनीतिक लड़ाई ट्विटर पर ही लड़ती रहती हैं। हाल ही में सुशील मोदी के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग के कारण ट्विटर ने उन्हें 17 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। राबड़ी देवी भी यदा-कदा ट्वीट करती हैं, जिसमें ज्यादातर उनके निशाने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्य सभा सदस्य सुशील कुमार मोदी होते हैं। सुशील मोदी भी राबड़ी को लेकर लालू की राजनीति की बखिया उधेड़ते रहते हैं। अब लालू-राबड़ी की एक और बेटी ट्विटर पर सक्रिय हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के परिवार में ब्याही गई राज लक्ष्मी यादव अब ट्विटर वॉर में कूद पड़ी हैं। उन्होंने मां राबड़ी देवी का बचाव करते हुए सुशील मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है- सृजन चोर ञ सुशील मोदी शर्म करो...

वे सुशील मोदी के उस ट्वीट का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि घरेलू महिला राबड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बनाकर क्या लालू यादव संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरूस्त करने की क्रांति कर रहे थे। राजलक्ष्मी यादव ने घरेलू महिला शब्द पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनकी मां राबड़ी देवी ने बिहार में सात सालों तक राजकाज चलाया।

माफिया मुख्तार अंसारी वाली बांदा की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा में सेंध, फरार हो गया एक बंदी

बांदा । पंजाब की रोपड़ जेल से माफिया मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के बाद बांदा जेल की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सोमवार को उस समय सामने आ गई जब एक विचाराधीन बंदी फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और हाईसिक्योरिटी के बावजूद बंदी के भाग जाने की सूचना के बाद जेल अफसरों में खलबली मच गई है। उपमहानिरीक्षक कारागार प्रयागराज ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही बंदी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगा दी हैं।

यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को कुछ दिन पहले ही पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर जेल में हाईसिक्योरिटी सिस्टम होने का दावा किया जा रहा था। बीस से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और अलार्म सिस्टम समेत हथियारबंद बंदी रक्षकों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद रविवार की

शाम जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदी बांदा के थाना गिरवां ग्राम बरसड़ा बुजुर्ग निवासी 22 वर्षीय विजय आरख फरार हो गया। उसके भाग जाने की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत भी सामने आ गई।

बांदा कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि बरसड़ा बुजुर्ग निवासी विजय अरख को गिरवां थाना पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तारी के बाद 6 फरवरी 2021 को जेल में दाखिल कराया था। वह रोजाना की तरह जेल के बाहर कृषि फार्म में काम करने के लिए अन्य बन्दियों के साथ बंदी रक्षकों की निगरानी में रविवार की दोपहर गया था। सभी बंदियों के साथ वह शाम को लौटा लेकिन रात करीब साढ़े आठ बजे जेल लॉकिंग के समय वह नहीं मिला।

अलार्म कराकर जेल के अंदर उसकी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बांदा को सूचित करने के बाद प्रकरण में कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आखिरी बार बंदी को रविवार की शाम पौने सात बजे के करीब जेल में देखे जाने की पुष्टि हुई है। कारागार और पुलिस की सर्च टीमें बंदी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना के बाद प्रयागराज मंडल के एडीजी जेल संजीव त्रिपाठी ने तत्काल जेल पहुंचकर घटना की जानकारी के बाद जांच के निर्देश दिए हैं।

शराब माफिया पर नकेल के लिए यूपी पुलिस ने कसी कमर, अब संयुक्त टीम बनाकर होगी छापेमारी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आए दिन सामने आ रही अवैध शराब से मृत्यु की घटनाओं पर डीजीपी मुख्यालय ने खासी नाराजगी जताई है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर आईना दिखाया है। स्पष्ट कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ऐसी घटनाएं हुई हैं, उससे साफ है कि जिलों में पुलिस द्वारा मिलावटी शराब की बिक्री को रोकने के लिए पूरे प्रयास और इंटेलीजेंस का उपयोग नहीं किया है। इसी वजह से ऐसी घटनाओं की कई जगह पुनरावृत्ति भी देखी गई है।

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने अपने पत्र में पुलिस कप्तानों से कहा है कि अवैध शराब के कारोबारियों और माफिया के खिलाफ अपने निर्देशन में कानूनी कार्रवाई कराएं। अवैध शराब के सेवन से होने वाली मौतों से कानून व्यवस्था बरकरार रखने में मुश्किल होती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसकी रोकथाम के लिए प्रशासनिक मजिस्ट्रेट, आबकारी अधिकारी व सीओ की संयुक्त टीम बनाकर शराब के ठेकों की नियमित जांच की जाए। जिलों में हर महीने क्राइम मीटिंग में आबकारी अधिकारियों को भी बुलाया जाए।

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि थाने के बीट स्तर के कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो, ताकि वह ऐसी गतिविधियों के बारे में थाना प्रभारी को सूचित करे और पर्याप्त पुलिस बल के साथ छापेमारी की जा सके। जरूरत पड़ने पर पूरे सर्किल के पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाए और उसकी रिपोर्ट पुलिस कप्तान को दी जाए। ऐसे अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमों की विवेचना जल्द पूरी कर चार्जशीट दाखिल कराएं और प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाएं। आरोपितों की गिरफ्तारी हो, उन पर ईनाम घोषित किया जाए।

प्रशांत कुमार ने कहा है कि यदि अवैध शराब के धंधे में किसी पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता हो तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी गांव में बार-बार ऐसे अपराधी पकड़े जाएं तो ग्राम चौकीदार को बर्खास्त करें। उप्र आबकारी अधिनियम में वर्ष 2017 में हुए संशोधन के मुताबिक जहरीली शराब से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में दोषियों के खिलाफ धारा-60क के तहत मुकदमा दर्ज हो, ताकि उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास व दस लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा दिलाई जा सके। साथ ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका लगाकर उनकी संपत्तियों को कुर्क भी किया जाए।

यूपी में 3 महीने में 10 करोड़ कोरोना टीके लगाने का लक्ष्य, जिलों को चिन्हित कर होगा सौ फीसद वैक्सीनेशन

लखनऊ । कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रित करने और तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द से जल्द जनता को टीके का सुरक्षा कवच दे देना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण को और तेज करते हुए तीन माह यानी जून, जुलाई और अगस्त में दस करोड़ टीके लगाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा है कि कुछ जिलों को चिन्हित कर वहां अभियान चलाकर सौ फीसद टीकाकरण कराया जाए।

कोरोना संक्रमण से बचाव और इलाज की समीक्षा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कहा कि प्रदेश में दो करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग में भी 30 लाख से अधिक युवाओं को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए वैक्सीनेशन को और बड़े पैमाने पर तेजी के साथ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जून, जुलाई व अगस्त में 10 करोड़ प्रदेशवासियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखकर काम किया जाए। जरूरत होने पर दो पालियों में टीके लगाने का काम कराया जाए।

वैक्सीन की सप्लाई चेन को रखें मजबूत – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई चेन को मजबूत रखें। वैक्सीन लगाने वालों को प्रशिक्षित कराया जाए। इस काम के लिए नर्सिंग के द्वितीय, तृतीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों व पैरामेडिकल के द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण कराएं। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया जाए कि वैक्सीन का वैस्टेज कम से कम हो।

चिकित्सा सुविधाओं के लिए पांच जोन में बांटा प्रदेश – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि सामुदायिक, प्राथमिक, उप स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ व वेलनेस सेंटर को मजबूत करने की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश को पांच जोन में बांटा गया है। जिला स्तर पर निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। कोविड बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पीडियाट्रिक आइसीयू और नियोनेटल आइसीयू की स्थापना तेजी से कराई जा रही है।

भ्रमण के दौरान किसी भी ओपीडी में जाएं चिकित्सा अधिकारी – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सीएमओ, एसीएमओ और डिप्टी सीएमओ भी ओपीडी में मरीजों को देखें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में एक-दो घंटे मरीजों को देखें। इससे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर होंगी। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपस्थित सभी डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ एप्रेन पहनें और नेम प्लेट जरूर लगाएं।

नौ जून से धीरे-धीरे अनलॉक हो सकता बिहार, मिलेगी और ज्यादा छूट

पटना । बिहार में आठ जून की रात 12 बजे तक लॉकडाउन-4 लागू है। इसके पहले सरकार अब अनलॉक पर मंथन कर रही है। सोमवार को सभी जिलों के डीएम से फीडबैक लेने के साथ ही वरीय अफसरों से विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। मंगलवार(8 जून) को अपराह्न 11:30 बजे लॉकडाउन को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त के साथ गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी और डीजीपी शामिल होंगे। इसके बाद सीमए नीतीश कुमार कुछ रियायतों के साथ अनलॉक की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अचानक ही सब कुछ अनलॉक नहीं होगा। बिहार में 31 मार्च के बाद संक्रमण दर काफी कम हुआ है। कोविड के दूसरे लहर की पीक के वक्त जहां एक दिन में पूरे राज्य से

15 हजार तक मामले मिले थे अब यह घटकर एक हजार हो गया है। पटना जिला में शनिवार को 100 से भी कम नए केस मिले हैं। जिसे देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर बिहार को अनलॉक करने पर विचार हो रहा है।

सूत्रों के अनुसार, नए आदेश में दुकानों को खोलने के लिए अधिक समय मिल सकता है। नौ जून से रात आठ बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी जा सकती है। वर्तमान में जरूरी समान के दुकान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुलते है। अन्य प्रतिष्ठान ऑल्टरनेट डे खुलते हैं। नौ जून से सभी तरह के प्रतिष्ठानों को खुलने की छूट दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान पहले की तरह ही नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा निजी कार्यालयों को भी कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। सरकार की सोच है कि धीरे-धीरे अनलॉक किया जाए, ताकि बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह की भीड़ न हो।

संक्रमण रोकने में प्रभावी रहा है लॉकडाउन- कोरोना संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन काफी प्रभावी रहा है। पांच मई को जब लॉकडाउन लगाया गया तो राज्य में हर दिन करीब 15 हजार मामले सामने आ रहे थे जो धीरे-धीरे घटते हुए अब करीब एक हजार तक आ गए हैं। अनलॉक से लोगों के लापरवाह होने की आशंका है, जिससे संक्रमण दर फिर बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार धीरे-धीरे ही छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है।

गाइडलाइन में हो सकते हैं ये बदलाव- सूत्रों की मानें तो फिलहाल स्कूल, कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 10वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बनाने और एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को सीमित छूट दी जा सकती है। इसके अलावा व्यापार में और छूट दी जा सकती है। मॉल्स, बाजार और सभी तरह की दुकानों को रात आठ बजे तक खुलने की छूट दी जा सकती है। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। शादी-समारोहों और श्राद्ध में कुछ ज्यादा लोगों को शामिल होने की छूट हो सकती है। वर्तमान में शादी या श्राद्ध में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। जिम, पार्क, स्टेडियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे।

समस्तीपुर के दिधरा पंचायत में करंट लगने से ससुर व पुत्रवधू की मौत

समस्तीपुर । पूसा थाना क्षेत्र के दिधरा पंचायत स्थित बिरौली गांव के सच्चिदानंद राय (उम्र 60 वर्ष) एवं पुत्र वधू मंजू कुमारी (उम्र 40 वर्ष) की मौत सोमवार की सुबह पंखे में करंट लगने से घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के समय परिवार के और सदस्य खेत में काम करने गए हुए थे आस-पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दी। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार घर में रखे स्टैंड फैन को हरिनारायण राय की पत्नी मंजू कुमारी घुमाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच पंखे में करंट आ गया। इसके कारण मंजू कुमारी को करंट लगी। वह पंखे में काफी देर तक चिपकी रह गई। उसे देख वहां मौजूद ससुर ने अपने पुत्रवधू को बचाने का प्रयास किया। वे उससे उसे हटाना चाह रहे थे। इस दौरान करंट ने उन्हें भी चपेटे में ले लिया। उनकी भी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक मंजू कुमारी को दो पुत्र शिवम एवं सत्यम है। दोनों पुत्र अपने मां एवं बाबा की याद में चित्कार कर बदहवास है। वही आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी मातम है।

एक ही साथ एक ही परिवार के दो लोगों की मौत होने से स्वजनों में चीख-पुकार मची है। घटनास्थल पर संपूर्ण ग्रामीण सहित पंचायत प्रतिनिधि मुखिया सुनील कुमार सुमन, सरपंच अमोद कुमार शर्मा, पंकज कुमार, संतोष कुमार सहित दर्जनों लोग जुटे हुए हैं। मुखिया सुनील कुमार सुमन के द्वारा दूरभाष पर सीओ को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है।

यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आरोप- सपा व कांग्रेस कहती है भाजपा की वैक्सीन, मत लगवाओ...

बरेली । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बरेली प्रवास का प्रयोजन कोविड संक्रमण में दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के परिवारों को ढांढस बंधाने का था। लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे की बैठक में वह विधानसभा चुनाव 2022 की नब्ज भी टटोली गई। मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के शासन को आपने देखा। अब योगी आदित्यनाथ का देख रहे हैं। वक्त था, जब सैफई खानदान, एक परिवार एक व्यक्ति राज्य को चलाता था। योगी शासन में कानून है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं किसी को बचा सकता हूं। गुनहगार हो तो सलाखों के पीछे जाओगे।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को आपने देखा। विपक्ष में रहते संकटकाल में सत्तापक्ष के साथ खड़े रहे। आज कोविड संक्रमण के संकटकाल में सपा, कांग्रेस कहती है कि वैक्सीनेशन भाजपा का है। मत लगवाओ...। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने बचा लिया। स्थिति नियंत्रित हो गई। मुख्यमंत्री निगेटिव होने के बाद भ्रमण पर रहे। अच्छा कार्य हुआ।

आज जनता राहत में है। बसपा के लिए साफ्ट कार्नर के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने परिश्रम की पराकाष्ठा और इमानदार छवि आपको कही नहीं मिलेगी। हमारा नेतृत्व सक्षम है।

उन्होंने बरेली प्रवास पर कहा कि कोविड में संगठन के पदाधिकारियों ने अपने परिवारों के मुखिया को खो दिया। ऐसे परिवारों पर सरकार का ध्यान केंद्रीत है। वैक्सीनेशन के साथ कोविड संक्रमण नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों की टीमें बनाकर सभी जिलों में भेजी जा रही है। पूरी भाजपा सेवाकार्य के लिए गांव-गांव चल रही है। मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। मंत्रीमंडल में फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सर्किट हाउस में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बरेली कोर कमेटी के साथ वर्चुअल बैठक में चर्चाएं की।

रेखा पटेल के घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री – सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी घोषित करने और भाजपा के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विचार चल रहा है। जल्द ही नाम की घोषणा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार रेखा पटेल के घर पहुंचे। उनके पति योगेश पटेल से मुलाकात की। उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दरम्यान रेखा पटेल के नाम पर मजबूती से चर्चा हुई। हालांकि हाइकमान के निर्णय को अंतिम मानने का आश्वासन दिया गया है।

स्व. केसर सिंह के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की – नवाबगंज के विधायक स्व. केसरसिंह के घर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं हरदोई, शाहजहांपुर में ऐसे परिवारों से मिलता हुआ आया हूं। जिन्होंने अपने मुखिया को इस दौर में खो दिया। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद होते हुए मेरठ और कासगंज जाऊंगा। पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक लगातार ऐसे परिवारों की चिंता कर रहे हैं।

मुंबई के बांद्रा में चरणबद्ध तरीके से शुरू हुए कोविड -19 लॉकडाउन को खोलने के बाद लोग बस के लिए कतार में इंतजार करते हुए।

बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन ने मुंबई में कोविड -19 प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हाल ही में चेन्नई के बाहरी इलाके वंडालूर में एक 9 वर्षीय शेरनी की संदिग्ध कोरोनावायरस संक्रमण से मौत के बाद अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क के निरीक्षण के दौरान।

एक नजर

अपराध के वक्त नाबालिग घोषित 13 दोषी आगरा जेल में अब भी बंद, रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन 13 दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है, जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है. याचिका के मुताबिक, ये सभी कैदी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ जेल में रखा गया है.

वकील ऋषि मल्होत्रा के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया कि 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद सभी 13 याचिकाकर्ताओं को अपराध किए जाने के समय किशोर घोषित किया गया था. यानी बोर्ड ने पाया था कि अपराध के समय इन सभी की आयु 18 वर्ष से कम थी. जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अमेंडमेंट एक्ट, 2006 के मुताबिक, केस के निपटारे के बाद भी उनकी किशोरावस्था को लेकर किसी भी समय याचिका दाखिल की जा सकती है. याचिका में कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड की ओर से फरवरी 2017 से इस साल मार्च के बीच याचिकाकर्ताओं को किशोर घोषित करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद इन सभी को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया.

भाजपा नेताओं को घेरने को कांग्रेसियों से पुख्ता सुबूत जुटा रही रायपुर पुलिस

रायपुर । टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस ने दिल्ली से कांग्रेस के आइटी सेल के एक लैपटाप की हार्ड डिस्क जब्त की है। इस हार्ड डिस्क की साइबर टीम के माध्यम से फारेंसिक जांच कराई जाएगी। रायपुर के सिविल लाइन थाने के प्रभारी आरके मिश्रा ने कहा कि साइबर टीम से जो रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस कांग्रेस के रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गौड़ा, रोहन गुप्ता और सौम्या वर्मा का बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस की इस कार्रवाई को मामले में आरोपित भाजपा नेताओं को पुख्ता साक्ष्य के साथ घेरने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह व भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा आरोपित हैं। राय में इससे पहले भी पात्रा के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को लेकर किए गए ट्वीट की वजह से एफआइआर दर्ज की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले को राजनीतिक मानते हुए सभी एफआइआर निरस्त करा दी थीं। यही वजह है कि पुलिस इस बार कांग्रेस नेताओं के बयान और हार्ड डिस्क के जरिये पुख्ता साक्ष्य एकत्र कर रही है, ताकि भाजपा नेताओं को कोर्ट से भी राहत न मिल सके।

नोटिस के बावजूद बयान देने नहीं आ रहे पात्रा- संबित पात्रा को पुलिस बयान लेने के लिए दो बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वह नहीं आए। पुलिस अब तीसरी बार नोटिस भेजने की तैयारी में है। वहीं, मामले के दूसरे आरोपित पूर्व सीएम डा. रमन सिंह पुलिस को अपना लिखित बयान दे चुके हैं।

यह है मामला- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह व भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के 18 मई के एक ट्वीट को लेकर एनएसयूआइ के प्रदेशाध्यक्ष आकाश शर्मा की लिखित शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। इसमें भाजपा के दोनों नेताओं पर इंटरनेट मीडिया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग के जाली लेटर हेड में फर्जी व मनगढ़ंत न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास करने का आरोप है।

कोवैक्सीन के मुकाबले कोवीशील्ड शरीर में बनाती है अधिक एंटीबॉडीज, शोध में हुआ खुलासा

नई दिल्ली । शरीर में वायरस के खिलाफ एंटी बॉडीज के निर्माण में कोवीशील्ड कोवैक्सीन से यादा असरदार है। एक ताजा स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोवीशील्ड इंसानी शरीर में कोवैक्सीन से अधिक एंटी बॉडीज का निर्माण करती है। ये ताजा स्टडी कोरोना वायरस इंड्यूस्ड एंटी बॉडीज टीट्रे (कोवेट) ने की है। इस शोध में उन हैल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया था जिन्होंने कोवीशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक ली थीं।

इस स्टडी के दौरान ये बात सामने आई कि कोवीशील्ड की पहली खुराक के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर कोवैक्सीन की तुलना में अधिक होता है। हालांकि इसको क्लीनिकल प्रेक्टिस में शामिल नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम में दोनों ही वैक्सीन का अछा प्रभाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोवीशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। किसी भी वैक्सीन की दोनों खुराक लेने पर जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बेहतर हैं। इस शोध को 552 स्वास्थ्यकर्मियों पर किया गया था। इसमें 325 पुरुष और 227 महिलाएं थीं। इनमें से 456 लोगों ने कोवीशील्ड और 96 ने कोवैक्सीन की पहली खुराक ली थी। इनमें से करीब 79 फीसद लोगों में सीरापॉजीटिव होने का पता चला। इस शोध के निष्कर्ष के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन वायरस पर अछे तरीके से काम कर रही हैं। आपको यहां पर ये भी बता दें कि मई में इस तरह का ही बयान ढ्ढष्टस्क्रके डीजी बलराम भार्गव ने भी दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कोवीशील्ड की पहली खुराक के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर तेजी से बढ़ता है वहीं कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर बढ़ता है। आपको बता दें कि देश में चल रहे टीकाकरण से अब तक करोड़ों लोगों को जानलेवा कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि सरकार ने कोवीशील्ड की दो खुराकों के बीच का अंतराल 6-8 सप्ताह बढ़ाकर 12-16 सप्ताह कर दिया है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कोवीशील्ड की पहली खुराक से ही इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। हालांकि कोवैक्सीन की दोनों खुराकों के अंतराल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लक्षद्वीप ने जापान को टुना मछली का निर्यात शुरू किया, प्रतिदिन 5 टन टोक्यो भेजने की तैयारी

तिरुअनंतपुरम । लक्षद्वीप प्रशासन ने बेंगलुरु के रास्ते अपने यहां की प्रमुख टुना मछली का जापान को निर्यात शुरू कर दिया है। टुना मछली की पहली खेप शनिवार को अगति हवाई अड्डे से बेंगलुरु लाई गई। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इसके निर्यात के लिए निजी क्षेत्र से हाथ मिलाया है। लक्षद्वीप के जिलाधिकारी एस असकर अली ने बताया कि हम जापान को टुना मछली का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। प्रशासन बेंगलुरु के रास्ते प्रतिदिन पांच टन टुना मछली टोक्यो भेजना चाहता है। वापसी में यह चार्टर्ड विमान बेंगलुरु से तमाम जरूरी चीजें लक्षद्वीप लाएगा। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में 7,197 रजिस्टर्ड मछुआरे हैं। ये मछुआरे मछली मारने के लिए 2,158 मोटरयुक्त नौका का इस्तेमाल करते हैं।

केंद्र ने कोच्चि-लक्षद्वीप पनडुब्बी केबल परियोजना के लिए शर्तों में किया बदलाव, भारतीय कंपनियों को मिला बराबरी का मौका

नई दिल्ली । केंद्र ने कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच 1900 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल प्रणाली बिछाने की अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक के लिए प्रमुख पात्रता शर्तों को बदल दिया है. यह कदम तब आया जब घरेलू दूरसंचार उद्योग निकायों ने दूरसंचार मंत्रालय और पीएमओ से शिकायत की थी कि वैश्विक निविदा के लिए पात्रता शर्तों ने भारतीय कंपनियों को समान अवसर नहीं दिया है.

पिछले दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल की 1072 करोड़ रुपये की परियोजना में लक्षद्वीप के सभी 11 द्वीपों को जोड़ने के लिए 200 जीबीपीएस प्रारंभिक यातायात क्षमता के साथ 6 फाइबर जोड़ी का उपयोग करके एक समर्पित केबल सिस्टम बिछाने शामिल है.

फिलहाल लक्षद्वीप को दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने का एकमात्र माध्यम उपग्रहों के माध्यम से है, लेकिन उपलब्ध बैंडविड्थ 1 जीबीपीएस तक सीमित है. परियोजना को लागू करने के लिए मार्च में एक वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन जल्द ही घरेलू कंपनियों से दूर हो गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि कठोर पात्रता शर्तों के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में तौला गया.

टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने डीओटी और पीएमओ को पत्र लिखकर कहा था कि इससे एकल विदेशी बोलीदाता की स्थिति हो सकती है.

क्या हैं खास बदलाव- दो प्रमुख पात्रता शर्तों को बदलते हुए अब निविदा में परिवर्तन किया गया है. बोली लगाने वाली कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संचयी कारोबार की आवश्यकता को 1,400 करोड़ रुपये से घटाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

पहले रखी गई एक और शर्त यह थी कि बोली लगाने वाली कंपनी या उसकी मूल / होल्डिंग कंपनी को पिछले 12 वर्षों में कम से कम दो वैश्विक पनडुब्बी परियोजनाओं को निष्पादित करना चाहिए था, जिनमें से एक दोहराया प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही थी.

पनडुब्बी लाइन रिपीटर्स और केबल को 500 किलोमीटर तक तैनात करने की शर्त पहले के टेंडर की तरह ही है, लेकिन इसकी तैनाती की गहराई को अब 3000 मीटर की आवश्यकता से 2000 मीटर में बदल दिया गया है. पिछले 12 वर्षों के दौरान कम से कम 1000 किमी रिपीटेड सबमरीन केबल और 2000 किमी नॉन-रिपीटेड सबमरीन केबल के निर्माण का अनुभव होने की स्थिति भी वही रहती है.

घरेलू उद्योग निकायों ने किया था विरोध- उद्योग निकायों ने शिकायत की थी कि परियोजना के लिए बीएसएनएल की निविदा पहले की चेन्नई-अंडमान निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी केबल परियोजना की तरह ही थी, जिसे एक ही बोली में एक जापानी संघ ने हासिल किया था. कोच्चि-लक्षद्वीप परियोजना को कोच्चि से मिनिकॉय तक एक पुनरावृत्त खंड और अन्य द्वीपों के बारह गैर-दोहराए गए खंडों के साथ निष्पादित किया जाना है.

भारतीय उद्योग निकायों ने परियोजना के एक खंड में दोहराई गई प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि प्रौद्योगिकी केवल कुछ विदेशी कंपनियों के पास उपलब्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले की शर्तें जैसे तीन साल- 1,400 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी कारोबार और 3000 मीटर की गहराई पर 1000 किलोमीटर के लिए पुनरावर्तक केबल लगाने के अनुभव की आवश्यकता भारतीय कंपनियों के लिए प्रकृति में प्रतिबंधात्मक थी.

हवाला पैसे के इस्तेमाल में भाजपा नेताओं का नाम, ई श्रीधरन की अगुवाई में पार्टी बना सकती है जांच कमेटी

तिरुवनंतपुरम । केरल में छह अप्रैल को हुए चुनावों में हवाला के धन के इस्तेमाल के आरोपों का सामना कर रही भाजपा इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. समिति के गठन और इसमें कौन-कौन शामिल होंगे, इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य प्रभारी में बातचीत जारी है.

जानकारी के मुताबिक, इस समिति में मेट्रो मैन के नाम से विख्यात ई श्रीधरन, आईपीएस जैकब थॉमस (सेवानिवृत्त) और आईएएस सीवी अनादा बोस (सेवानिवृत्त) के शामिल होने की संभावना है.

दूसरी ओर, भाजपा ने रविवार को माकपा के नेतृत्व वाली प्रदेश की वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार पर उसके खिलाफ त्रिशूर जिले में एक राजमार्ग पर हुई चोरी के सिलसिले में बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया. कोचि में प्रदेश भाजपा की कोर समिति की बैठक से पहले आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि कोडाकारा डकैती मामले में आरोपी वाम दलों से संबंधित थे और पुलिस माकपा की तरफ से एक समुचित सियासी अभियान चला रही है. अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन का मजबूती के साथ समर्थन करते हुए पार्टी ने यह भी कहा कि एलडीएफ सरकार द्वारा उन्हें व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ मिथ्या प्रचार किया जा रहा है. भाजपा नेताओं ने कोचि शहर पुलिस की उस कार्रवाई की भी निंदा की जिसके कारण पार्टी की कोर समिति की बैठक के स्थल को एक होटल से बदलकर उसकी जिला समिति के कार्यालय में करना पड़ा.

क्या है हवाला पैसा का मामला : दरअसल यह मामला उस वक्त सामने आया, जब शमजीर समसुद्दीन ने 7 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई. इसमें शमजीर ने कहा कि जब वह कोझीकोड से कोचि जा रहे थे, उसी दौरान कोडकारा फ्लाइओवर पर एक गिरोह ने उनकी कार को रोककर उसमें रखे 25 लाख रुपए लूट लिए. पुलिस शिकायत में सिर्फ 25 लाख रुपए के लूट की बात कही गई थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो यह बात सामने आई कि यह रकम 3.5 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है. यह भी शक जताया गया कि यह हवाला का पैसा था.

असम में कोवैक्सिन की भारी किल्लत, वैक्सीनेशन सेंटर्स का चक्कर लगा रहे लोग, नहीं मिल रही डोज

नई दिल्ली । गुवाहाटी के बैसिष्ठ डेका कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज पाने की उम्मीद में हेंगराबारी मेडिकल यूनिट वैक्सीन सेंटर का पिछले पांच दिनों से दौरा कर रहे हैं. ये शहर का एकमात्र स्थायी वैक्सीन सेंटर है, जिसके पास कोवैक्सिन की सप्लाई है. 48 वर्षीय बैसिष्ठ ने कहा, 'मैं पिछले पांच दिनों से इस सेंटर के चक्कर लगा रहा हूं. हालांकि इस सेंटर में एक दिन में केवल 100 ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है क्योंकि राज्य में कोवैक्सिन की काफी कमी है'.

बैसिष्ठ डेका की दूसरी डोज लेने की 42 दिन की समय सीमा पहले ही बीत चुकी है. उन्होंने कहा, 'यह मेरा 43वां दिन है. पहले मैंने सोनापुर में कोशिश की, जहां मुझे वैक्सीन की पहली डोज मिली थी. हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास वैक्सीन नहीं है. जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से मैं यहां वैक्सीन की दूसरी डोज पाने की कोशिश में लगा हूं'. डेका ने बताया, 'पहले में 100 लोगों में शामिल न हो सका, लेकिन आज मैं सुबह 5 बजे आया और वैक्सीन की दूसरी डोज ली'.

दूसरी डोज वालों का वैक्सीनेशन पहले- असम सरकार ने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देना बंद कर दिया है ताकि दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए वैक्सीन की कमी न हो. राज्य में कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके पास कोवैक्सिन का स्टॉक उपलब्ध है, हालांकि इसकी कीमत 1,200 रुपये है, जो कई लोगों के वैक्सीनेशन में एक बाधा बन रही है.

गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लोडर अजॉय डेका कहते हैं, 'मेरी समय सीमा इस हफ्ते खत्म हो रही है. मैंने अपने आवास के पास वैक्सीन सेंटर्स के कई चक्कर लगाए. मुझे सरकार की मदद चाहिए क्योंकि मैं वैक्सीन के लिए 1200 से 1300 रुपये खर्च नहीं कर सकता'. मालूम हो कि राज्य में कई वरिष्ठ नागरिक पहली डोज लेने के बाद कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो कोवैक्सिन की दूसरी डोज नहीं ले सके. इनमें से कई लोग कॉमरेड यानी कई बीमारियों से पीड़ित हैं.

राज्य में अब तक 34.36 लाख लोगों का वैक्सीनेशन- वैक्सीनेशन अभियान के शुरुआत में असम सरकार ने कम से कम 1.78 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था. हालांकि राज्य में अब तक 34.36 लाख लोगों या 19.30 प्रतिशत लोगों को ही आंशिक रूप से वैक्सीन लगाई गई है.

राज्य में अभी तक केवल 8.45 लाख यानी लगभग 4.74 प्रतिशत का ही दोनों डोज के साथ वैक्सीनेशन हुआ है. असम में 4 जून तक कोविशील्ड और कोवैक्सिन की 42.81 लाख डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें 80.82 प्रतिशत से अधिक कोविशील्ड डोज और 18.69 प्रतिशत कोवैक्सिन शामिल है.

'अब इन दवाओं को लेने की जरूरत नहीं', कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली । भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसे लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कोरोना बीमारी के इलाज को लेकर अपनी गाइडलाइंस में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत बिना लक्षण वाले और हल्के मामलों के लिए एंटीपीयरेटिक (बुखार के लिए) और एंटीट्यूसिव (ठंड लगने पर) को छोड़कर बाकी सभी दवाओं को हटा दिया गया है. इसी के साथ, नई गाइडलाइंस में जरूरी न होने के मरीजों को सीटी स्कैन न कराने की भी सलाह दी गई है. गाइडलाइंस में बॉडी हाइड्रेशन के साथ सही खानपान पर जोर दिया गया है.

27 मई को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में उन सभी दवाओं को प्रभावी ढंग से हटा दिया गया, जिन्हें डॉक्टर बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए भी लिख रहे थे. इन दवाओं में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, मल्टीविटामिन आदि शामिल हैं. नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को इनमें से किसी दवा की जरूरत नहीं है. जबकि कोरोना के अलावा पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए दवाएं जारी रखी जानी चाहिए.

कब ले सकते हैं कौन सी दवा- हल्के मामलों में बुखार, सांस फूलने,

ऑक्सीजन लेवल या किसी भी लक्षण पर खुद निगरानी रखने की सलाह दी गई है. नई सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना के लक्षण दिखने पर लोग एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव दवाएं ले सकते हैं, वहीं खांसी के लिए 5 दिनों तक दिन में दो बार 800 एमसीजी की डोज पर बुडेसोनाइड ले सकते हैं. इन सब के अलावा किसी और दवा की जरूरत नहीं है. अगर लक्षण बने रहते हैं या और बिगड़ते हैं, तो मरीज की तुरंत जांच की जानी चाहिए.

जरूरी न होने पर न करवाएं सीटी स्कैन- सरकार की नई गाइडलाइंस में डॉक्टरों से कहा गया है कि वे जरूरी न होने के मरीज को सीटी स्कैन कराने की राय भी न दें. मालूम हो कि कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि सीटी स्कैन मशीन से निकलने वाले रेडिएशन काफी नुकसानदायक होते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं. वहीं, मास्क, हाथों की स्वच्छता और फिजिकल डिस्टेंस के पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए मरीजों को बॉडी हाइड्रेशन के साथ स्वस्थ और संतुलित खानपान की सलाह दी गई है. इसी के साथ, मरीजों और उनके परिवारों को फोन, वीडियो-कॉल आदि के जरिए जुड़े रहने और पॉजिटिव बातचीत करने के लिए भी कहा गया है.

देश में कोरोना संक्रमण के हालात- देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है. आज पिछले 61 दिनों में सबसे कम 1,00,636 नए केस आए हैं. देश में कोविड से मृत्यु दर 1.20 फीसदी है और रिकवरी रेट 93.94 फीसदी है. एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 14 लाख हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोविड से अब तक 3,49,186 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. रविवार को तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 20,421, केरल में 14,672, महाराष्ट्र में 12,557 और कर्नाटक में 12,209 नए मामले सामने आए. इन चारों राज्यों में एक्टिव केस की संख्या 8,44,974 है, जो देश के कुल एक्टिव मामलों का 60 फीसदी है.

एम्फोटेरिसिन-बी के इंजेक्शन से बिगड़ी ब्लैक फंगस के मरीजों की हालत, अस्पताल में मची हड़बड़ी

सागर । मध्य प्रदेश के सागर जिले में ब्लैक फंगस मरीजों में एम्फोटेरिसिन-बी के शॉट दिए जाने के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया की शिकायत सामने आई है। यहां जिले के सरकारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती 27 मरीजों को एम्फोटेरिसिन-बी का इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उनमें इसका कुछ प्रतिकूल असर देखने को मिला है। इनमें हल्का बुखार, कंपकंपी और उल्टी की शिकायत देखने को मिली है, जिसके बाद फंगस के इलाज में अहम दवा एम्फोटेरिसिन-बी के इस्तेमाल पर तत्काल मेडिकल कॉलेज में रोक लगा दी गई।

मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ उमेश पटेल ने कहा, वर्तमान में, 42 मरीज बीएमसी के म्यूकोर्मिकोसिस वार्ड में भर्ती हैं। इनमें से 27 रोगियों को एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन दिए गए थे। इंजेक्शन लगने के बाद, रोगियों को हल्का बुखार, कंपकंपी और उल्टी जैसी शिकायतें होने लगी। घटना के तुरंत बाद इंजेक्शन का उपयोग बंद कर दिया गया। हालांकि पटेल ने कहा कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है और डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, घटना के बाद बीएमसी अधीक्षक और डीन हरकत में आ गए और प्रभावित मरीजों का रोगसूचक उपचार तुरंत शुरू कर दिया गया। सभी मरीजों की हालत स्थिर है और डरने की जरूरत नहीं है। पटेल ने कहा, मरीजों को एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन के बदले दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है। म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस एक फंगल इंफेक्शन है। वातावरण में उपस्थित फंगस के संपर्क में आने से लोग म्यूकोर्मिकोसिस की चपेट में आ जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, काटने, खरोंचने, जलने या किसी और वजह से शरीर में हुए जख्म के माध्यम से यह फंगस त्वचा में प्रवेश कर जाता है और इसके बाद यह त्वचा पर भी विकसित हो सकता है। इस बीमारी की चपेट में यादातर वो लोग आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं या संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा मधुमेह के कारण जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि घातक बीमारी के इलाज के लिए प्रमुख दवा एम्फोटेरिसिन-बी की उपलब्धता अब बढ़ाई जा रही है

प्राथमिकता के आधार पर गर्भवतियों को लगे टीका, डाक्टरों ने सरकार से की सिफारिश

नई दिल्ली । कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की भी मौत हुई है। इसको देखते हुए एक रिपोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। डाक्टर यामिनी सरवाल के नेतृत्व में दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों के एक दल ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि मातृ और शिशु मृत्युदर में कोरोना के कारण और वृद्धि नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए उच प्राथमिकता वाले समूह में शामिल किया जाए। भारत समेत सभी देशों में कोरोना टीकाकरण को गर्भवती महिलाओं की चिकित्सकीय देखरेख में शामिल करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए तय किए गए किसी भी प्राथमिकता समूह में नहीं रखा गया है। इनके टीकाकरण को लेकर भी नीति स्पष्ट नहीं है। टीका लगवाने का फैसला गर्भवती महिलाओं पर ही छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट में गया है कि सामान्य महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के बाद यादा खतरा रहता है, इसलिए इन्हें टीके का सुरक्षा कवच दिया जाना जरूरी है।

दूसरी तरफ, एम्स में सोमवार से दो से 18 वर्ष की आयु के बचों पर कोरोना टीके का परीक्षण शुरू हो जाएगा। आठ हफ्ते में इस परीक्षण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण में भारत बायोटेक और आइसीएमआर की कोवैक्सीन का बचों के रोग-प्रतिरोधी तंत्र पर असर का अध्ययन किया जाएगा।

कंगना रनौत

ने शेयर की पोस्ट कोविड केयर स्टोरी, बताया कैसे रखें अपना ख्याल

बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अलग-अलग मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपने कोरोना पॉजिटिव (Kangana Ranaut Post Covid Care) होने की जानकारी दी थी. कोरोना संक्रमित पाए जाने के कुछ ही दिनों में वह ठीक भी हो गई थीं. अब जब कंगना महामारी (Kangana Ranaut Instagram) से पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं तो उन्होंने फैंस के साथ अपनी पोस्ट कोविड केयर स्टोरी भी शेयर की है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद वह कैसे अपना ख्याल रख रही हैं.

कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह पोस्ट कोविड केयर पर बात करती नजर आ रही हैं. वीडियो में कंगना कहती हैं- %मैं अपनी कोरोना की जर्नी के बारे में बताती आई हूं और आज मैं आपको कोरोना रिकवरी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. कोरोना जैसे मैंने आपको कहा एक आम साधारण सर्दी-जुकाम होता है, वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा. लेकिन, जो रिकवरी है, इसमें मेरे साथ कुछ शॉकिंग चीजें हुईं, जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं कीं.'

'अक्सर हमने देखा है कि बचपन में जब भी हम बीमार हुए. जैसे कि मुझे पीलिया हो गया था, एक बार मेरी टांग टूट गई थी. तो हम देखते हैं कि जब भी हम इस तरह की दुर्घटना से रिकवर होते हैं तो चाहे कम समय में रिकवर हो, चाहे ज्यादा रिकवर हो. लेकिन, जब रिकवर होने लगता है तो वह लगातार रिकवर होता जाता है. लेकिन, जो कोरोना है इसमें जो एक शॉकिंग चीज जो मैंने नोटिस की वह है कि यह फोर्स रिकवरी देता है. मेरी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के 1-2 दिन में ही मुझे लगा कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं. अब मैं कोई भी काम चाहे वह वर्कआउट हो, एक्टिंग शिफ्ट हो. मैं जिस क्षमता से काम कर सकती थी, अब भी कर सकती हूं. लेकिन, वह एक फॉल्स रिकवरी थी.

जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो पता चला कि मैं फिर से एक बहुत जबरदस्त रिलेप्स की शिकार हो जा रही हूं. ऐसा लग रहा है कि जैसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है. गला दर्द होने लगा और बुखार भी आने लगता है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ये वायरस है वह जैनेटिकली मोडिफाइड है. ट्रीटेड है. जो मेरा अनुभव रहा है कि जैसे ये वायरस आपके शरीर के अंदर कुछ डैमेज कर रहा होता है. कुछ लोगों को पर्मानेंट डिमेंशिया हो रहा है, कुछ को हार्ट अटैक हो रहा है. कुछ लोग तो सिंपली मर जा रहे हैं.

कंगना आगे कहती हैं - 'ये संक्रमण हमारे शरीर का जो म्यूचल रिस्पॉन्स है, उसको म्यूट कर देता है. ये जो फॉल्स रिकवरी देता है, उसी के चलते लोग मर जा रहे हैं. इसकी वजह कुछ भी हो सकती है. ब्रीदिंग फेलियर, हार्ट अटैक या फिर ऑर्गन फेलियर. यानी जितना जरूरी इस वायरस से रिकवर होना है उतना ही जरूरी है कि बाद में भी अपना ख्याल रखा जाए. क्योंकि, इसका असली असर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद दिखाई देता है. तो मेरा ये अनुभव रहा. ठीक होने के बाद कई बार तो बिना किसी लक्षण के मैं फिर से जबरदस्त रिलेप्स हो गई. तो मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि जो रिकवरी पीरियड है, उसे अनदेखा ना करें. रेस्ट करें और अपना पूरा ख्याल रखें. स्टीमलेते रहें.

कटरीना कैफ

को कबूल हैं विक्की कौशल, दोनों अपने रिश्ते को जल्द दे सकते हैं नाम

बॉलीवुड से एक खुशखबरी आने वाली है. दो सेलिब्रिटी अपने रिश्ते को नाम दे ना चाहते हैं. हम बात कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की. हालांकि दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी दिनों से चर्चा है, लेकिन इस बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं पता चल पाया है. बॉलीवुड के गलियारों से ऐसी खबर आ रही है कि दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को कबूल करने वाले हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों के मुताबिक कटरीना कैफ और विक्की कौशल एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले चुके हैं. खबर है कि दोनों जल्द ही सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे सकते हैं. हालांकि विक्की के पापा ने इस फैसले से पहले ठीक से सोचने समझने की सलाह दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, कटरीना भी विक्की को लेकर बहुत पजेसिव हैं. उन्होंने अपने को स्टार के साथ अंतरंग सीन करने से मना किया है. कटरीना नहीं चाहती कि विक्की लव सीन करें.

बता दें कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल काफी समय से एक दूसरे के साथ देखे जा रहे हैं. बॉलीवुड की कई पार्टियों और फंक्शन में दोनों साथ-साथ जाते हैं. दोनों ने अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया था. अपने भाई-बहनों के साथ मस्ती करते हुए फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए थे.वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल ने 'मनमर्जियां', 'लव' जैसी शानदार फिल्में की हैं. विक्की की अपकमिंग फिल्म 'सरदार उद्यम सिंह' है. इसके अलावा मानुषी छिल्लर के साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं. वहीं, कटरीना कैफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म 'सूर्यवंशी' जल्द ही रिलीज होने वाली हैं. इसके अलावा 'फोन भूत' में ईशान खट्टर के साथ तो 'टाइगर 3' में सलमान खान के साथ नजर आएंगी.

करीना कपूर डिलीवरी के चार महीने बाद ही शेप में लौंटी, 'MIRROR SELFIE' में दिखा फिट लुक

प्रेग्नेंसी के बाद हर एक महिला का वजन बढ़ जाता है, जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता. लेकिन करीना कपूर (Kareena Kapoor) अपने दूसरे बेटे के जन्म के चार महीने बाद ही शेप में लौट आई हैं. एक्ट्रेस ने फरवरी के महीने में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था. करीना अपनी प्रेग्नेंसी (Pregancy) के दौरान भी काफी एक्टिव थीं और अक्सर फिटनेस से जुड़ी बातें लोगों के साथ शेयर करती रहती थीं. दिलचस्प बात यह है कि करीना बेटे के जन्म के एक महीने बाद ही काम पर लौट आई थीं. अब एक्ट्रेस ने अपनी एक ऐसी फोटो शेयर की है, जिसमें वे अपने पुराने वाले रूप में दिख रही हैं. वे तस्वीर में अपना फिट लुक दिखा रही हैं.

करीना ने यह फोटो दो दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की थी. यह एक मिरर सेल्फी है, जिसमें एक्ट्रेस का वजन काफी कम नजर आ रहा है. वे काफी स्लिम नजर आ रही हैं. फोटो के ब्रैकग्राउंड में करीना और सैफ का खूबसूरत स्वीमिंग पूल दिख रहा है. साथ में, योगा मेट भी दिख रही है, जिससे लगता है कि करीना ने योगा के बाद यह फोटो शेयर की थी. एक्ट्रेस ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, मिरर ग्लास में चीजें जितनी पास होती हैं, उससे ज्यादा करीब नजर आती हैं. इसलिए दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अब यह सामान्य बात है.

बता दें कि लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद करीना और सैफ ने 2012 में शादी कर ली थी. इस कपल ने 2016 में अपने पहले बच्चे तैमूर का स्वागत किया था. लॉकडाउन के चलते बेबो ज्यादातर वक्त परिवार के साथ घर पर बिता रही हैं. काम की बात करें तो एक्ट्रेस फिल्म लाल सिंह चड्ढा में जल्द ही नजर आएंगी, जो हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिन्दी रीमेक है. यह फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी.

जूही चावला को कोर्ट की फटकार, Petition को पब्लिसिटी स्टंट बताकर लगाया भारी जुर्माना

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) ने बीते सोमवार को 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी (zG Wireless Network) को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने खारिज कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है. खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस भारत में 5जी वायरलेस नेटवर्क की स्थापना के खिलाफ हैं. उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का लोगों, जीवों, पैड़-पौधों पर होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की थी.

खबरों के अनुसार, एक्ट्रेस ने अपने वकील दीपक खोसला के जरिये याचिका में कहा था कि 5जी टेक्नोलॉजी का इंसानों पर बुरा असर देखने को मिलेगा और इससे धरती के ईको सिस्टम पर बेहद बुरा असर पड़ेगा. अगर 5जी योजनाएं पूरी होती हैं, तो इसके असर से कोई भी जीव बच नहीं पाएगा. साथ में, याचिका में यह साबित करने का अनुरोध किया गया है कि यह 5जी टेक्नोलॉजी कैसे लोगों और पेड़-पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी.

खबरों की मानें तो कोर्ट ने मामले में अपनी सुनवाई में इसे एक्ट्रेस का पब्लिसिटी स्टंट बताया है. उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस की याचिका तथ्यों से परे थी, यह पूरी तरह कानूनी सलाह पर टिकी हुई थी. कोर्ट ने जूही पर अदालत की कार्यवाही का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में 20 लाख का जुर्माना लगाया है. बता दें कि जूही ने कोर्ट की सुनवाई का एक वीडियो लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था.

दो दिन पहले एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे अपनी याचिका को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात कह रही थीं. वीडियो में एक्ट्रेस अपने चिर-परिचित अंदाज में बोलती दिख रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा है कि कुछ ट्वीट पढ़कर उनकी हिम्मत बढ़ी है, जिसमें उनके काम की सराहना हुई है.

विराट , रोहित को भी अभ्यास की कमी से निपटना होगा : वेंगसरकर

मुंबई, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि अभ्यास की कमी शीर्ष खिलाड़ियों के लिए भी भारी पड़ती है। इसलिए यह नहीं समझना चाहिये कि भारतीय टीम के कप्तान कोहली को इससे निपटना नहीं पड़ेगा। वेंगसरकर ने कहा कि कोहली और रोहित बहुत अच्छी लय में हैं पर प्रतिस्पर्धी मैचों की कमी के कारण दौरे की शुरूआत में डब्ल्यूटीसी फाइनल में उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। वेंगसरकर ने कहा, वह (कोहली) लंबे समय से टीम के साथ है और अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। कोहली और रोहित विश्वस्तरीय खिलाड़ी है और उन्हें अपने प्रदर्शन और भारत की जीत पर गर्व होता होगा। इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कहा, अच्छी बात यह है कि दोनों शानदार लय में है। मुझे लगता है कि मैच अभ्यास की कमी उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम दौरे के शुरूआती टेस्ट में ऐसा हो सकता है।

वहीं उनका मानना है कि कीवी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों से मिले अभ्यास का लाभ मिलेगा

वेंगसरकर ने कहा, टीम इंडिया एक बेहतर टीम है और शानदार लय में है। न्यूजीलैंड के साथ फायदे की बात यह है कि उनकी टीम ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहती है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले उन्हें दो टेस्ट मैच खेलने को मिल रहे हैं। इससे उन्हें खिताबी मुकाबले में हालात के अनुसार ढ़लने में सहायता मिलेगी। इस पूर्व कप्तान ने कहा, मैं मानता हूं कि भारतीय टीम को इस टेस्ट (डब्ल्यूटीसी फाइनल) से पहले दो-तीन मैच खेलने चाहिये थे ताकि परिस्थितियों के मुताबिक अपने को ढाल सकें।

उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों की तरह गेंदबाजों को भी मैच अभ्यास की जरूरत है। वेंगसरकर ने कहा, बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों के लिए भी मैच खेलने और मैदान में समय बिताने की सलाह दी जाती है। आप भले ही नेट अभ्यास करते हो और मैच की परिस्थितियों के बारे में जानते हो लेकिन मैदान पर मैच खेल खेलने से मिला अभ्यास अलग होता है।

गावस्कर इसलिए नहीं बने कोच

मुम्बई, (एजेंसी)। महान बल्लेबाज गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। वह विश्व के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। इसके बाद भी गावस्कर अभी भी भारतीय टीम के कोच नहीं रहे हैं। अब इस पूर्व कप्तान ने स्वयं कोच न बनने के कारणों का खुलासा किया है। गावस्कर ने कहा कि

मैं अपने को कोच के तौर पर फिट नहीं पाता हूं क्योंकि कोच या चयनकर्ता बनने के लिए आपको हर गेंद देखनी पड़ती है और मेरे अंदर इतना संयम नहीं है। मैं लगातार देखने की जगह टुकड़ों में मैच देखता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं खेल रहा था और आउट होने के बाद पवेलियन लौटता था। फिर भी लगातार मैच नहीं देखता था। कुछ देर मैच देखने के बाद मैं चेंज रूम में चला जाता था और या तो किताब पढ़ता था या पत्रों का जवाब देता था। मैं कभी भी गेंद-दर-गेंद मैच देखने में रुचि नहीं रखता था। गावस्कर कोचिंग से दूर रहे पर इसके बाद भी कठिन दौर में वह क्रिकेटरों को सलाह देते आये हैं। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ भी अपने करियर के समय मुश्किल दौर में गावस्कर से सलाह लेते थे। सचिन और द्रविड़ ने तो कई बार इस बारे में कहा है। इसपर गावस्कर ने कहा कि हां, ये बात सही है कि पुराने टीम इंडिया के खिलाड़ी मेरे पास आते थे। खासतौर पर सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण और सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने कई बार मुझसे बात की। मुझे उनसे खेल के बारे में बात करना काफी अच्छा लगता था। उनके खेल को लेकर मेरी जो भी राय होती थी, मैं उन्हें बताता था।

मियामी में मुक्केबाज लॉगन पॉल व मैवेदर एक प्रदर्शन मैच में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए।

रॉबिन्सन को निलंबित किये जाने के विरोध में उतरे रुट

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने आठ साल पुराने विवादित ट्वीट के कारण गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को निलंबित किये जाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने मैच के बाद कहा कि रॉबिन्सन ने गेंदबाजी के साथ ही बल्ले से भी अपना योगदान दिया। उसने अपनी प्रतिभा दिखाई है और उसे टेस्ट मैच खेलने को मिला। वह टेस्ट क्रिकेट में सफलता हासिल कर सकता है लेकिन जो मैदान के बाहर हो रहा है वह स्वीकारीय नहीं है हमारे खेल के लिए।

रूट ने कहा कि हम सभी जानते हैं। उसने ड्रेसिंग रूम इस बारे में सभी खिलाड़ियों को बताया। उसने जितने भी साथी खिलाड़ी हैं उन्हें और मीडिया वालों को भी इस बारे में बताया। उसे अपनी गलती का अहसास हो गया है और उसने इसका पश्चाताप भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि वह टीम में कैसा है और वह अपनी असल पहचान बता रहा है।

रूट ने आगे कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उन ट्वीटस को विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं पता लोग इसे कैसे देख रहें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ओली हमारे ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है और हम उसे अपना समर्थन देंगे। वहीं इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर डेब्यू करने वाले रॉबिन्सन को डेब्यू मैच के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने निलंबत कर दिया था। उन पर साल 2012 में रंगभेद और नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले ट्वीट करने के आरोप हैं। मैच के दौरान ही रॉबिन्सन के कुछ विवादित ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे जो उन्होंने सालों पहले किए थे। रॉबिन्सन ने इसके लिए मैच के दौरान ही माफी भी मांगी पर माफी के बाद भी उन्हें ईसीबी ने निलंबित कर दिया।

टीम इंडिया के लिए विदेशी मैदान भाग्यशाली रहे हैं

लंदन, (एजेंसी)। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून को साउथम्पटन में खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस टूनार्मेंट में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसका कारण हाल में उसके अच्छे प्रदर्शन के साथ ही पुराने आंकड़े भी हैं। अब तक देखा गया है कि विदेशी मैदान हमेशा से ही टीम इंडिया को रास आये हैं। भारतीय टीम ने पहला खिताब विदेशी जमीन पर ही जीता था। इतना ही नहीं इंग्लैंड के मैदान टीम इंडिया के लिए अच्छे साबित हुए हैं। ऐसे में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर यहां जीत दर्ज कर पुराने रिकार्ड को बनाये रखना चाहेगी।

टीम इंडिया ने साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली आईसीसी एकदिवसीय ट्रॉफी भी जीती थी। कपिल देव की कप्तानी में टीम ने तब एकदिवसीय विश्व कप में वेस्टइंडीज को हराकर सबको हैरान कर दिया था। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का पहला खिताब भी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जीता थी। साल 2002 में बारिश के कारण दो दिन हुए फाइनल का परिणाम नहीं निकल सका था। ऐसे में दोनों टीमें संयुक्त विजेता बनी थीं। तब गांगुली ही टीम के कप्तान थे।

टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप का पहला खिताब भी विदेशी जमीन पर ही जीता था। 2007 में टूनार्मेंट के पहले सीजन के मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में हुए. जोहानिसबर्ग में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हराया था। महेन्द्र सिं धोनी टीम के कप्तान थे।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 23 जून को एक रिजर्व डे भी रखा गया है पर इसका इसका उपयोग तभी होगा जबकि पांच दिन में खेल के पूरे ओवर नहीं हो सकेंगे। इसका फैसला मैच रेफरी करेगा. अगर मैच ड्रॉ या टाई होता है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगी। अब तक सिर्फ एक बार 2002 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में संयुक्त विजेता देखने को मिला था.

विराट बतौर कप्तान अब तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं। ऐसे में वे इस कमी को दूर करना चाहेंगे। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के ओवरऑल क्रिकेट रिकॉर्ड को देखें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों के बीच तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 185 मुकाबले गए हैं। इसमें टीम इंडिया को 82 में जीत मिली है जबकि न्यूजीलैंड ने 69 मैच जीता है।

बढ़ते टी20 लीग मुकाबलों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को खतरा : डुप्लेसिस

जोहांसबर्ग, (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फॉफ डुप्लेसिस ने कहा है कि टी20 लीग मुकाबलों की बढ़ती संख्या से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए क्रिकेट बोर्ड को लीग और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा।

डुप्लेसिस ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) से पहले कहा, टी20 लीग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खतरा हैं क्योंकि यह तेजी से बढ़ रही हैं। जहां शुरूआत में दुनिया भर में सिर्फ 2 लीग थी जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर साल में 4, 5, 6, 7 लीग बन गई है।

डु प्लेसिस ने कहा कि अगर खेल के संरक्षक के लिए अभी सुधारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो भविष्य में फुटबॉल की तरह ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी घरेलू लीगों के आगे कमजोर पड़ जाएगा। यह एक बड़ी चुनौती है। हो सकता है कि 10 साल के समय में क्रिकेट भी फुटबॉल की तरह हो जाएगा जहां आपके पास अपने विश्व कार्यक्रम होते हैं और बीच में दुनिया भर में ये लीग होती हैं जहां खिलाड़ी खेल सकते हैं।

इस अनुभवी बल्लेबाज ने इसको लेकर वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो का उदाहरण दिया और कहा कि भविष्य में कई और खिलाड़ी भी आगे जाकर फ्रीलांस क्रिकेटर बन सकते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान उनकी संबंधित राष्ट्रीय टीमों को होगा। उन्होंने कहा, वेस्टइंडीज शायद पहली टीम है जिसने ऐसा करना शुरू किया है। उनके सभी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टीम से टी20 घरेलू सर्किट में चले गए। इसलिए वेस्टइंडीज टीम ने अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों को खो दिया। अब सही यह दक्षिण अफ्रीका के साथ भी शुरू हो रहा है।

सेन फ्रांसिस्को में मेघा गेनी अमेरिकी महिला गोल्फ टूर्नामेंट में खेलती हुईं।

पूर्व कप्तान हुसैन ने जीत का प्रयास न करने के लिए इंग्लैंड टीम को फटकारा

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने ड्रॉ हुए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में अपने टीम के रुख की आलोचना की है। हुसैन ने कह कि मैच देखकर ऐसा लगा जैसे कि केवल मेहमान टीम न्यूजीलैंड ही जीत का प्रयास कर रही थी जबकि मेजबान टीम का रुख नकारात्मक दिखा। इंग्लैंड को अंतिम 2 सत्रों में मैच जीतने के लिए 273 रनों की जरुरत थी।

कप्तान जो रूट और डोमिनिक सिबली ने इंग्लैंड की ओर से प्रयास किये पर उनकी बल्लेबाजी धीमी रही। सिबली ने 207 गेंदों पर 60 रन बनाए, जो वर्ष 2000 के बाद इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज की सातवीं सबसे धीमी अर्धशतकीय पारी थी। हुसैन ने कहा, ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही पक्ष इसे जीतने के लिए उत्सुक था और इसलिए कीवी कप्तान केन विलियमसन अंत में भी सकारात्मक बने रहे। वह 15 ओवर रहते हुए भी ड्रॉ का प्रयास कर सकते थे पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए प्रयास किया। नासिर ने कहा कि इंग्लैंड जीत के लिए क्यों नहीं गया, आपको इसे संदर्भ में रखना होगा। उन्होंने अपने आखिरी तीन टेस्ट मैच गंवाए क्योंकि उनके पास कोई जोस बटलर, कोई बेन स्टोक्स जैसा कोई और खिलाड़ी नहीं था।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि इंग्लैंड टीम में जीतने का इरादा नहीं था और हाल के खेलों के लिए मेजबान के धीमे रुख ही जिम्मेदार रहे। हुसैन ने कहा, वे खुद को टेस्ट क्रिकेट में अकसर 20-3 पाते हैं, इसलिए आपको इंग्लैंड की यह टीम कहां है और कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है इसकी बड़ी तस्वीर देखनी होगी।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कम से कम जीतने की कोशिश करें, कुछ इरादा दिखाएं। हुसैन चाहते हैं कि उनकी टीम न तो ज्यादा आक्रामक और न ही ज्यादा रक्षात्मक क्रिकेट खेले। उन्होंने कहा, आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए उनकी बहुत आलोचना हुई, अब वे रक्षात्मक क्रिकेट खेलते हैं, यह एक या दूसरा होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, 70 ओवरों में आप दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं और फिर अगर आप थोड़ी परेशानी में हैं तो आप इसे वापस खींच सकते हैं।

कनेरिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जडेजा को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बताया

लाहौर, (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया के अनुसार न्यूजीलैंड के साथ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी साबित होंगे। कनेरिया ने 18 से 22 जून तक साउथेम्प्टन में होने वाले इस खिताबी मुकाबे के लिए जडेजा को 3डी खिलाड़ी बताया है और कहा कि उन्हें किसी भी कारण से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 10 मैचों में जडेजा ने 469 रन बनाने के साथ ही 28 विकेट भी लिए हैं। कनेरिया के अनुसार तेजी से रन बनाना, अहम मौकों पर विकेट लेना और सटीकता के साथ रन आउट करने की क्षमताओं के कारण जडेजा टीम इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गेंदबाज एक अहम भूमिका निभाते हैं फिर चाहे आप कोई सा भी फॉर्मेट खेल रहे हो। यदि वह विकेट ले रहे हैं, तो मैच में जीत मिलना तय है। वहीं यदि हम जडेजा की बात करें तो वह 3डी खिलाड़ी हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसे आप बाहर नहीं कर रख सकते। वह अहम मौकों पर बड़े विकेट निकालने की क्षकता रखते हैं।

वह रन बनाएंगे, साझेदारी को लंबा खींचेंगे और फील्डिंग के दौरान कुछ अद्भुत रन आउट भी करेंगे। इसी वजह से जडेजा फाइनल में भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहेंगे। इंग्लैंड में जडेजा ने पांच टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने दो अर्धशतकों सहित कुल 276 रन बनाए हैं। इसके साथ ही 15 विकेट भी लिए।

बेटे अगस्त्य के साथ समय बिता रहे हार्दिक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। ऐसे में अभी हार्दिक घर पर ही अपने बेटे अगस्त्य और नताशा स्टेनकोविक के साथ समय बिता रहे हैं। पंड्या की पत्नी नताशा स्टेनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जसमें दोनों बेटे अगस्त्य के साथ वाटर टब में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। नताशा ने हार्दिक को टैग करते हुए दिल वाला इमोजी के साथ लिखा, वाटर बेबीज। इससे कुछ दिन पहले हार्दिक अपने 10 महीने के बेटे अगस्त्य को घर में उंगली पकड़कर चलना सीखा रहे थे। इसका वीडियो भी नताशा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हार्दिक ने हाल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें वह सुपर फंकी लुक में दिखाई दे रहे थे। वहीं नताशा ने अपने पति की तस्वीर पर कॉमेंट बॉक्स में आग वाली इमोजी पोस्ट की थी। हार्दिक के टीम इंडिया के साथी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी कॉमेंट करने में पीछे नहीं रहे। बुमराह ने लिखा, ईगल गैंग। गौरतलब है कि सर्जरी से उबरने के बाद पंड्या का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरुप नहीं रहा है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है। हार्दिक का आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। कोरोना की वजह से आईपीएल 2021 को बीच में ही रोक दिया गया।

आठ साल पुराने ट्वीट्स के कारण गेंदबाज रॉबिन्सन निलंबित

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के युवा गेंदबाज ओली रॉबिन्सन अपने आठ साल पुराने नस्लवादी और सेक्सिस्ट ट्वीट्स के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिये गये हैं। रॉबिन्सन को साल 2012 और 2013 में किए अपने इन ट्वीट्स के कारण पदार्पण मैच के बाद ही बाहर होना पड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने इन ट्वीट्स को लेकर रॉबिन्सन ने माफी भी मांगी थी। इसके बाद भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने उन्हें रियायत न देते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। यह गेंदबाज अब तब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पायेगा जब तक की जांच पूरी न हो जाये।

रॉबिन्सन को एजबेस्टन में गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले ही बाहर कर दिया गया था। 27 वर्षीय खिलाड़ी रविवार को इंग्लैंड कैंप से रवाना होकर ससेक्स लौटेंगे। इससे पहले गत बुधवार को रॉबिन्सन ने अपने पुराने ट्वीट्स के लिए माफी मांगते हुए कहा था, मेरे करियर के अब तक के सबसे बड़े दिन पर मैं 8 साल पहले पोस्ट किए गए नस्लवादी और सेक्सिस्ट ट्वीट्स से शर्मिंदा हूं, जो आज सार्वजनिक हो गए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नस्लवादी नहीं हूं और मैं सेक्सिस्ट नहीं हूं।

उन्होंने कहा था कि मुझे अपने कार्यों पर गहरा खेद है और मुझे इस तरह की टिप्पणी करने के लिए शर्म आती है। मैं किसी भी व्यक्ति से बिना शर्त माफी मांगना चाहता हूं, मेरे साथियों और पूरे खेल में भेदभाव का मुकाबला करने और जागरूकता का दिन रहा है। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा था कि ओली ने एक कठिन सबक सीखा है हालांकि उसने जो किया है वह अस्वीकार्य है पर उसे उसे बात का पछतावा है। इस तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की और कुल 7 विकेट लिए थे। जिसमें पहली पारी में चार जबकि दूसरी पारी में तीन विकेट थे। (4/75) और (3/26) अपने नाम किए थे। इसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए 42 रन भी बनाए थे। रॉबिन्सन ने यह भी कहा था कि इस मैच में अपने प्रदर्शन के लिए मेरी चर्चा होनी थी पर यह निराशाजनक है कि विवादास्पद ट्वीट्स के कारण मुझे याद किया जा रहा है।

स्लोवेनिया में जर्मनी के लूकास निमेसा यूरो 21 के फाइनल में शुरूआती गोल करते हुए।